● वर्ष-4
● अंक-37
रायपुर, शुक्रवार
20 सितंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› टिकाऊ खेती आज की आवश्यकता...

पाकिस्तान में कांग्रेस-एनसी गठबंधन की सराहना , कांग्रेस-एनसी के घोषणापत्र से खुश

कोई नहीं करा सकती 370 की वापसीः मोदी

कटरा। कटरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हुंकार भरा है। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा किहम जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती है। आपको बता दें कि 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। हालांकि, राज्य के विपक्षी दल लगातार अनुच्छेद 370 की मांग कर रहे हैं और वह इस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में भी हैं।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस को दिया गया हर वोट पीडीपी और एनसी के घोषणापत्र को लागू करेगा। उन्होंने कहा कि वे धारा 370 को वापस लाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वे घाटी में फिर से खून-खराबा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कांग्रेस-एनसी गठबंधन की सराहना हो रही है। पाकिस्तान कांग्रेस-एनसी के घोषणापत्र से बेहद खुश है और उसने खुलकर समर्थन दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलकर कांग्रेस-एनसी गठबंधन के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि उनका एजेंडा पाकिस्तान जैसा ही है। कांग्रेस और एनसी यहां जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री ने वादा करते हुए कहा कि मां के इस पावन धाम से मैं आपको एक और बात के लिए फिर से आश्वस्त करता हूं। जम्मू कश्मीर को ?हम फिर से राज्य बनाएंगे। हमने इसकी घोषणा संसद में ही कर दी थी। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद कमजोर हुआ है। हम अब क्षेत्रीय स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके समर्थन से जम्मू-कश्मीर जल्द ही आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा।

उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि मोदी आज कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है... हम जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस को लेकर जम्मू-कश्मीर में भले ही, उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश (पाकिस्तान) इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। पाकिस्तान में कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस के अलायंस की बल्ले-बल्ले हो रही है। इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत प्रभावित है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35 को लेकर कांग्रेस और ह्रष्ट का एजेंडा वही है, जो पाकिस्तान का एजेंडा है यानी कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है।

अब्दुल्ला ने कांग्रेस को जेब में डाला, युवाओं के लिए खोद रहे कब्र-महबूबा

जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग होगी। राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुफ्ती साहब (मुफ्ती मोहम्मद सईद) ने बहुत कोशिश की, 50 साल में कांग्रेस को खड़ा किया (जम्मू-कश्मीर में)। जब कांग्रेस यहां स्थापित हुई, तो फारूक साहब ने राजीव गांधी से हाथ मिलाया और कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया। उन्होंने अभी-अभी एक व्यक्ति को मौत की सजा दी है, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी। उन्होंने 1987 के चुनावों में धांधली की और ऐसी स्थिति बना दी कि जम्मू-कश्मीर के लोग अभी भी युवाओं के लिए कब्र खोद रहे हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र-शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटे जाने के बाद से वहां पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वर्ष 2022 में परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 87 से बढ़कर 90 हो गई, जिनमें से 47 सीट कश्मीर घाटी में और 43 सीट जम्मू में हैं। चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवारों की अधिक संख्या को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां), कंग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने आरोप लगाया कि इन्हें दिल्ली से समर्थन मिल रहा है। तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कुल 365 उम्मीदवारों ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है।

राहुल गांधी के विरूद्ध शिकायतें दर्ज

सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा ने आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा गत 10 सितम्बर को अमरीका में दिए जन विरोधी ब्यानों के विरूद्ध तीन पुलिस शिकायतें दर्ज करवाई। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आज एक पत्रकार सम्मेलन में बताया की कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं पर आज देश हो या विदेश उनके ब्यान सामाजिक वैमनस्य बिगाड़ने वाले होते हैं।

इसी कड़ी में उन्होने गत 10 सितम्बर को अपने अमरीका प्रवास के दौरान भारत में सिख समुदाय में असुरक्षा के भाव को लेकर झूठी भ्रमक ब्यानबाज़ी के साथ ही देश में संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित जाति को मिल रहे आरक्षण को लेकर टिपण्णी की। राहुल गांधी के द्वारा अमरीका में दिये गये इन ब्यानों से ना सिर्फ भारत में सिख समुदाय में बल्कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति में तनाव एवं घबराहट उत्पन्न हुई है तो वहीं विदेश में बैठ कर राहुल गांधी द्वारा इस तरह की ब्यानबाज़ी से भारत की छवि धूमिल हुई है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की खेदपूर्ण है की राहुल गांधी अपने भ्रमक ब्यानों के लिए देश से माफी मांगने की जगह कांग्रेस नेताओं से और आगे विवादित ब्यान दिलवा कर देश वैमनस्य बढ़ा रहे हैं। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की राहुल गांधी के ब्यान से सिख समुदाय में भारी रोष है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

इसी को लेकर आज दिल्ली भाजपा के सिख प्रकोष्ठ संयोजक सरदार चरणजीत सिंह लवली ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1), 197 (1)(सी), 197 (1)(डी) के अंतर्गत पुलिस शिकायत दर्ज की है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

इसी तरह राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने से जुड़े ब्यान से अनुसूचित जाति जाति समाजों में भारी रोष है जिसके चलते आज दिल्ली भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संयोजक श्री सी.एल. मीणा ने संसद मार्ग थाने में और अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष श्री मोहनलाल गिहारा ने पंजाबी बाग थाने में अलग अलग शिकायतें दर्ज करवाई हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं की हमारी शिकायतों के आधार पर जांच की जाये और राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई हो।

मुख्यमंत्री ने जनदर्शन में हजारों लोगों की सुनी समस्याएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में मरीजों को इलाज के लिए तत्काल आर्थिक सहायता मंजूर करने के साथ ही दिव्यांगों को मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल, वॉकर सहित अन्य सहायक उपकरण प्रदान की। जनदर्शन कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न इलाकों से सभी आयु वर्ग एवं समाज के हजारों लोग अपनी समस्या एवं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। जनदर्शन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ.

भारत में मनी लांड्रिग की रोक से खुश एफएटीएफ

नई दिल्ली। देश में गैरकानूनी तरीके से पैसे का लेन-देन करने, अवैध कमाई को पकड़ने और आतंकी संगठनों तक वित्तीय संसाधनों की पहुंच को रोकने के लिए भारत का रिकार्ड बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए भारत के उपायों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। भारत ने धन शोधन निरोधक और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने की प्रणाली लागू की है जो कई मायनों में प्रभावी है। एफएटीएफ ने भारत के बारे में कहा कि धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की आवश्यकता है। गैर लाभकारी क्षेत्र का आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में उपयोग न हो इसके लिए सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में धन शोधन का मुख्य स्रोत देश के भीतर की अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होता है। ये जोखिम मुख्य रूप से धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिसमें साइबर-फ्रॉड, करप्शन और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है। देश को अदालती प्रक्रियाओं के समापन तक लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के बैकलॉग को संबोधित करने की आवश्यकता है। हालांकि, भारत को अभियोजन को समाप्त करने और आतंकवादी वित्तपोषकों को दोषी ठहराने और उचित रूप से प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जी-7 ग्रुप की ओर से बनाई गई निगरानी एजेंसी है। इसकी स्थापना इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और विनाशकारी हथियारों के प्रसार और फाइनैंस को रोकना है। यह ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। यह निगरानी के बाद देशों को टारगेट देता है, जैसे आतंकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, हथियारों की तस्करी की रोकथाम के लिए कानून बनाने की सलाह देता है।

प्रमुख समाचार

तिरुपति प्रसाद में जानवर की चर्बी

नई दिल्ली। लाखों-करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र तिरुपति तिरुमाला मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं में पशु वसा और मछली का तेल होने की पुष्टि लैब रिपोर्ट के जरिए हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस (वाईएसआरसीपी) सरकार पर तिरुपति लड्डू बनाने में पशु वसा और घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अब, पशु आहार और दूध उत्पादों के परीक्षण पर केन्द्रित एक निजी प्रयोगशाला एनडीडीबी की रिपोर्ट में तिरुपति मंदिर के लड्डू और अन्नदानम के सैम्पल की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से भेजे गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट, जिन्हें परीक्षण के लिए गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को भेजा गया था। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने कहा कि नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रमाणित करती है.

भाजपा केवल हिंदुओं का इस्तेमाल करती है: आदित्य

मुंबई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत दौरे को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है। आदित्य ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत दौरे से पहले सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में आदित्य ने कहा कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को हिंसा का सामना करना पड़ा। फिर केंद्र सरकार बीसीसीआई पर इतनी नरमी क्यों बरत रही है और दौरे की अनुमति क्यों दे रही है? यदि नहीं, तो क्या विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में हिंसा के बारे में लगातार सोशल मीडिया और समाचार आउटलेट में आई घटनाओं से सहमत है? भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल को ट्रोल बताते हुए ठाकरे ने कहा कि यहां उनके ट्रोल दूसरे देश बांग्लादेश में हिंसा के बहाने भारतीयों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं, जबकि बीसीसीआई उसी बांग्लादेशी टीम की क्रिकेट के लिए मेजबानी कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने इस हिंसा के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया है, वे बीसीसीआई से बात क्यों नहीं करते.

पन्नू मामला को हल्के में नहीं ले सकतेः भारत

नई दिल्ली। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा अमेरिका में भारतीय सरकार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दायर करने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि जैसा कि हमने पहले कहा है, ये पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप हैं। अब जब यह विशेष मामला दर्ज किया गया है। इससे अंतर्निहित स्थिति के बारे में हमारे विचार नहीं बदलते हैं। मैं केवल आपका ध्यान इस विशेष मामले के पीछे के व्यक्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसका इतिहास सर्वविदित है। मैं इस तथ्य को भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि जिस संगठन का यह व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, वह एक गैरकानूनी संगठन है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर उच्च-स्तरीय समिति पहले से काम कर रही है। मिसरी ने कहा कि इस संगठन को1967 के गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ऐसा घोषित किया गया है और ऐसा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण किया गया है।

नवादा अग्निकांडः मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 16 गिरफ्तार

नवादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जांच आदेश के बाद बिहार पुलिस ने गुरुवार को बिहार के नवादा में आगजनी के आरोपी 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी नंदू पासवान भी शामिल है। मुख्य आरोपी कथित तौर पर बिहार के नवादा जिले के एक भू-माफिया का हिस्सा है। नवादा अग्निकांड पर बिहार की राजनीति गरमा गई है और विपक्षी नेता आरोपियों को तत्काल सजा देने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। यहां तक ??कि नीतीश कुमार की एनडीए पार्टनर एलजेपी (रामविलास) के चिराग पासवान ने भी घटना की निंदा की और न्यायिक जांच की मांग की। चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा कि बिहार के नवादा में दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलित टोले के लगभग 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रावधान करें। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि मामले की न्यायिक जांच की भी मांग करता हूं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने की हिमाकत भी न करे।

यूक्रेन पहुंचे भारत के हथियार, रूस हो गया इससे नाराज

नई दिल्ली। भारत के हथियार निर्माता जो हथियार यूरोप को बेच रहे हैं, वो यूरोप के जरिए यूक्रेन पहुंच रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रूस भारत के इस कदम से नाराज हो गया है। हालांकि अब भारत ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया किया गया था कि भारतीय हथियार निर्माताओं द्वारा बेचे जाने वाले तोप के गोले यूरोपीय ग्राहकों द्वारा यूक्रेन भेजे गए हैं। मॉस्को ने इस पर ऐतराज जताया था। लेकिन इसके बावजूद नई दिल्ली ने यूक्रेन से हथियारों के व्यापार को नहीं रोका है। इससे पहले आज, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ग्यारह भारतीय और यूरोपीय सरकार और रक्षा उद्योग के अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय ने इसे अटकलबाजी और भ्रामक करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा ति इसमें भारत द्वारा उल्लंघन का संकेत मिलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और इसलिए यह गलत और शरारतपूर्ण है।

केजरीवाल का आतिशी-दांव बिगाड़ेगा विपक्षी रणनीति!

राज कुमार सिंह

हार -जीत तो दिल्ली के मतदाता तय करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के दांव से कई निशाने साधने की कोशिश की है। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा, केजरीवाल का इस्तीफा मांगती रही, पर उन्होंने दिया अपनी रणनीति के मुताबिक। 13 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने और 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया। 17 सितंबर को इस्तीफा हो गया और 'आप' विधायक दल का नया नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनादेश के जरिए दिल्ली के मतदाताओं द्वारा उन्हें 'ईमानदार' मान लेने के बाद ही पद लेंगे। जाहिर है, आतिशी चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगी।

वैसे नेतृत्व के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन में उन्होंने तो यह भी कह दिया कि विश्वास जताने के लिए वह आभारी हैं, पर दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वह हैं केजरीवाल। केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही नवंबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। जाहिर है, चुनाव का समय चुनाव आयोग तय करेगा, पर केजरीवाल ने उसके लिए अपना रणनीतिक दांव अभी से चल दिया है। बेशक सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल को सिर्फ जमानत मिली है, वह शराब घोटाले में बरी नहीं हुए पर दोषी भी तो करार नहीं हुए हैं!ज़मानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुईयां ने सी.बी.आई. पर तल्ख टिप्पणियां भी कीं, जिसने ई.डी. केस में जमानत मिलते ही केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तत्परता दिखाई थी, लेकिन जमानत की शर्तों के मद्देनजर मुख्यमंत्री की वैसी भूमिका निभा ही नहीं सकते थे, जिसके लिए केजरीवाल जाने जाते हैं। न नीतिगत फैसले ले सकते थे और न ही लोक-लुभावन घोषणाएं कर सकते थे।

फिर वह चौथी बार जनादेश के लिए मतदाताओं के बीच किस आधार पर जाते? दूसरी ओर भाजपा 'जमानत पर रिहा अभियुक्त' करार देते हुए अभियान चलाती। 'आप' का चुनाव प्रचार सफाई देने में ही निकल जाता। लोकपाल मुद्दे पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनाने वाले केजरीवाल की छवि आक्रामक नेता और वक्ता की रही है। अपने और पार्टी के भविष्य की लड़ाई रक्षात्मक मुद्रा में लडऩा जोखिम भरा हो सकता था। इसलिए उन्होंने 'पद-मुक्त' होकर पुरानी आक्रामक छवि में लौटना बेहतर समझा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर केजरीवाल, राजनीतिक प्रतिशोध की शिकार 'आप' के संयोजक के रूप में खासकर भाजपा के विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाएंगे। अभियान हरियाणा विधानसभा चुनाव से शुरू होकर दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड तक जारी रहेगा।

हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत न मिलने से तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी पर बढ़ गई नरेंद्र मोदी सरकार की निर्भरता के मद्देनजर इन राज्यों के विधानसभा चुनावों का महत्व जगजाहिर है। जनादेश भाजपा के अनुकूल नहीं आया तो विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के तेवर और आक्रामक हो जाएंगे। नई लोकसभा के अभी तक हुए 2 सत्रों में और संसद के बाहर भी विपक्ष के तेवर सत्तापक्ष को लगातार घेरने वाले नजर आ रहे हैं। पूछा जा सकता है कि इन राज्यों में दिल्ली के अलावा तो कहीं भी 'आप' का जनाधार नहीं है। बेशक, लेकिन हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है।

लोकसभा चुनाव साथ लडऩे वाली कांग्रेस ने कई दौर की बातचीत के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन से इंकार कर दिया। अब कांग्रेस की तरह 'आप' भी 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के आक्रामक प्रचार का खतरा कांग्रेस आलाकमान समझ सकता है। ऐसे में अभी भी हरियाणा में तालमेल का रास्ता खोजा जा सकता है, क्योंकि गठबंधन राजनीति में कांग्रेस वहां जैसा बोएगी, वैसा ही उसे दिल्ली में काटना भी पड़ेगा। अगर हरियाणा विधानसभा में आप शून्य है, तो दिल्ली विधानसभा में वही हैसियत कांग्रेस की है। परस्पर तल्खी से तो विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के भविष्य पर सवालिया निशान ही लगेगा।

विपक्ष के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकने वाले केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में भी 'आप' के लिए कुछ सीटों का दबाव बना सकते हैं। वैसे उससे परे भी देखें तो भाजपा की हार विपक्ष की ही जीत होगी। फिर भी यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि केजरीवाल के लिए दिल्ली की सत्ता सबसे अहम् है। बेशक पंजाब में भी 'आप' प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ़ है। गुजरात और गोवा में भी उसने दम दिखा कर एक दशक के अंदर ही राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया है, पर 'आप' और केजरीवाल की पहचान दिल्ली से जुड़ी है, जहां वह लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ है। ऐसे में दिल्ली की सत्ता गंवाने का जोखिम आत्मघाती हो सकता है। इसीलिए केजरीवाल ने 'श्रीमान ईमानदार' की छवि बहाल करने के लिए रक्षात्मक के बजाय आक्रामक होने का विकल्प चुना है।

इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चेहरा बनाए जाने की अटकलें थीं, जो अमेठी हारने के बाद नया ठिकाना तलाश रही हैं, पर उससे पहले ही केजरीवाल ने आतिशी को आगे कर दिया है। शानदार शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाली आतिशी ने कम समय में ही दिल्ली में जैसी छवि बनाई है, उन पर वैसे हमले कर पाना तो भाजपा के लिए मुश्किल ही होगा, जैसे हमले केजरीवाल पर करने की रणनीति उसने बनाई थी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी।

फॉरेस्ट रेंज में अवैध कब्जा, 50 डिसमिल वन भूमि अतिक्रमण मुक्त

बलरामपुर। रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के कनकपुर गांव में वन विभाग की टीम ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए लगभग पचास डिसमिल वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया है।वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कनकपुर में ललन गुप्ता नाम के व्यक्ति ने प्लांटेशन एरिया में लगाए गए पौधों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद अवैध तरीके से वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया था। वन विभाग के तरफ से नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण खाली नहीं कर रहा था और कब्जे को बढ़ाते जा रहा था।इसके बाद गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जे को हटाया है साथ ही घर को जल्द खाली करने का नोटिस दिया गया है।

इस मामले में डिप्टी रेंजर विजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कनकपुर में कंपार्टमेंट क्र 3446 अंतर्गत प्लांटेशन एरिया में पौधों को नष्ट कर अवैध कब्जा किया जा रहा था। विभाग के नोटिस जारी करने के बावजूद कब्जा खाली नहीं करने पर हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए लगभग 50 डिसमिल वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया है।

डिप्टी रेंजर विजय कुमार सिंह ने कहा प्लांटेशन एरिया में अवैध तरीके से एक कच्चा मकान भी निर्माण किया गया है। मकान को जल्द खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अगर जल्द कब्जा खाली नहीं किया गया तो फिर विभाग के द्वारा बेदखली की कार्रवाई किया जाएगा।

बलरामपुर रामानुजगंज जिले में हरे-भरे जंगलों को उजाड़कर वन भूमि पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। वन विभाग भी लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। बीते तीन महीने से रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में वन विभाग के तरफ से अवैध कब्जा करने वालों पर लगातार कार्रवाई करते हुए वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।

वनों की दुर्दशा, वन भूमि पर अतिक्रमण को हटाने सड़क पर उतरीं महिलाएं, कलेक्टर-डीएफओ को सौंपा ज्ञापन

कोरिया। जिले में वनों की दुर्दशा और वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरीं। इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जंगलों में जारी अवैध अतिक्रमण और अवैध कटाई पर अंकुश लगाने की गुहार लगाई।

कोरिया वन मंडल की वनभूमि पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की मांग के लिए ग्रामीण महिलाओं के साथ भाजपा समर्थित कोरिया जिला पंचायत की सदस्य, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कलेक्टोरेट और वन मंडल कार्यालय पहुंची। वन मंडलाधिकारी और कोरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंप सरकार से जंगल बचाने आग्रह किया।

वन अधिकार पट्टा पाने की होड़ में जंगलों का सफाया हो रहा है, वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों में इसको लेकर काफी रोष है। इस संबंध में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र हुई और ज्ञापन देने वन मंडल कोरिया तथा कलेक्टोरेट पहुंचे। जहां उन्होंने ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है।

बैकुंठपुर जिला मुख्यालय पहुंची महिलाओं का कहना था कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में वन भूमि पर कब्जा हो रहा है, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वन भूमि पर अतिक्रमण कर खेत और घर बनाए जाने से पशुओं की चराई एवं निस्तार भूमि कम हो जा रही है। इससे ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने अपनी बात वन विभाग के डीएफओ और कोरिया कलेक्टर के सामने रखा है।

दशहरा दिवाली से पहले बोनस की मांग, संयुक्त ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन

भिलाई। संयुक्त ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में बोरियागेट में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बोनस, 39 महीने का एरियर्स, आरआईएनएल के सेल में विलय को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बोनस मिलना चाहिए। इस प्रदर्शन में बीएएमएस, इंटक, सीटू , एटक, एचएमएस, एक्टू लोईमू एवं इस्पात श्रमिक मंच शामिल हुए।

भिलाई इस्पात मजदूर संघ के चन्ना केशवलू ने बताया कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा बोनस मिलना चाहिए। कम से कम वेतन के डीए बेसिक के आधार पर त्योहार पर बोनस मिलना चाहिए।

एटक के महासचिव विनोद सोनी ने बताया कि बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट देश का सबसे बेहतर स्टिल प्लांट है। कोरोना काल में भी कर्मचारियों ने बेहतर काम किया है, लेकिन अबतक यहां वेतन समझौता नहीं हो पाया है। 39 महीने का एरियर नहीं दिया गया है।

एटक महासचिव विनोद सोनी ने कहा दिवाली करीब है। बोनस का समय है। अबतक बैठक नहीं बुलाई गई है। कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। पिछली बार से ज्यादा बोनस चाहिए।

एचएमएस महासचिव प्रमोद मिश्रा ने कहा कि बोनस, 39 महीने का एरियर और आरआईएनएल का विनिवेशीकरण को रोकना यह हमारी तीन मांग है। एचएमएस महासचिव प्रमोद मिश्रा ने यह भी कहा कि सरकार और प्रबंधन श्रमिकों के हित का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठेकाकरण बढ़ाया जा रहा है। सरकारें अब कंपनियां नहीं चलाना चाहती हैं। श्रमिकों और सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है।

कोरबा में शराब दुकान हटाने को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन

बोलीं- गंदे-गंदे कमेंट करते हैं शराबी

कोरबा। मुड़ापार बाईपास मार्ग पर मौजूद कम्पोजिट शराब दुकान को हटाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के साथ क्षेत्र के लोग एकजुट हो गए हैं। शराब दुकान के बाहर तालाबंदी कर लाठी-डंडे स लैस होकर बैठे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस मौके पर तैनात है। लोगों ने स्पष्ट रुप से कह दिया है कि जब तक शराब दुकान को हटाया नहीं जाता वे मौके से नहीं हटेंगे। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर डटी हुई हैं। उनका आरोप है कि शराब दुकान के कारण उनका मार्ग से आना जाना बंद हो गया है। उनका कहना है कि मार्ग से गुजरने पर शराबी गंदे-गंदे कमेंट करते हैं।

जोहार छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रमुख संगठन मंत्री सुरेश राठौर ने बताया कि मुड़ापार, अमरियापारा, शारदा विहार और रामनगर के लोग शराब भट्टी को हटाने के लिए कई बार जिला प्रशासन और जो एसपी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, जहां उनकी मांगे पूरी नहीं होने के कारण आज उन्हें आंदोलन पर बैठना पड़ा है। कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने बताया घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए संबंधित आबकारी विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है। किसी तरह की घटना न हो इसे लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है।

बाईपास मार्ग होने के कारण भारी वाहनों का परिचालन मार्ग पर हमेशा रहता है, जिससे मार्ग पर हादसों की आशंका काफी बढ़ जाती है। मार्ग पर कई बार हादसे भी हुए है। मुड़ापार शराब दुकान को बंद करने की मांग को लेकर इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन हर बार प्रशासन केवल आश्वासन ही देता है। देखने वाली बात होगी कि इस बार इस शराब दुकान को लेकर प्रशासन क्या रुख अपनाता है।

बस्तर में टीचर की हत्या के बाद से डर के साये में जी रहे शिक्षक

■ कलेक्टर से लगाई सुरक्षा की गुहार

जगदलपुर। बस्तर जिले के अंदुरुनी इलाको में आदिवासी बच्चों से लेकर हर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा की लौ जलाने वाले शिक्षकों को अपनी जान को लेकर काफी खतरा महसूस हो रहा है, जिसका कारण है कि बीते दिनों नक्सलियों के द्वारा एक शिक्षा दूत की हत्या होना। इसे लेकर शिक्षकों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि जान जोखिम में डालकर धुर नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों के बच्चों को शिक्षित-दीक्षित कर रहे शिक्षा दूत अब नक्सलियों के निशाने पर हैं।

जिले के अंदरुनी इलाकों तक जहां प्रशासन की भी पहुंच नहीं है, वहां रहकर बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाने वाले ये शिक्षा दूत दरअसल स्थानीय शिक्षित बेरोजगार हैं, जिन्हें 11 हजार रुपये मासिक मानदेय पर यह जॉब ऑफर किया गया है। 2005 से जान जोखिम में डालकर अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे इन शिक्षा दूतों पर नक्सलियों ने नजर टेढ़ी कर ली है और यही इनकी चिंता का सबसे बड़ा सबब बन गया है।

नक्सल प्रभावित पंचायत सिलगेर के सरपंच कोरसा सन्नू कहते हैं कि शिक्षा दूतों ने जो बीड़ा उठाया है, वह नि:संदेह मानवता की सेवा कहा जाएगा, लेकिन नक्सली अब इनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। मुखबिरी का आरोप लगाते हुए इनकी हत्याएं की जा रही हैं। एक के बाद एक तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। परिजनों को भी धमकियां मिल रही हैं।

10 वीं और 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर रोजगार की तलाश कर रहे आदिवासी युवाओं को जब शिक्षा दूत बनाया गया तो उन्हें गांव में ही रहकर यह काम करने का बेहतर अवसर लगा। अब जब जान खतरे में है तो वे सोच में पड़ गए हैं। कलेक्टोरेट तक पहुंचने के लिए संभवत: मानदेय को बहाना इसलिए बनाया गया, क्योंकि यदि वे प्रशासन से नक्सलियों की सीधी शिकायत करते तो तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर जैसी स्थिति बनती। बहरहाल इस मसले को शासन-प्रशासन किस तरह से हैंडल करेगा, यह देखने लायक बात होगी।

लोहारीडीह कांड : कबीरधाम एएसपी विकास कुमार सस्पेंड

कबीरधाम। 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को बुधवार देर रात कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने सस्पेंड कर दिया। आईपीएस अधिकारी विकास कुमार कबीरधाम जिले में बीते 7 माह से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर थे। इन्हे जंगल रेंगाखार थाना क्षेत्र लोहारीडीह कांड के मामले में सस्पेंड किया गया है।

दरअसल, बीते रविवार को लोहारीडीह गांव में हुए हत्याकांड व आगजनी के एक आरोपी की बुधवार को कवर्धा के जेल में संदिग्ध मौत हो गई थी। इस आरोपी को कवर्धा के जिला जेल में रखा गया था। आरोपी की सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में आने से पहले इसकी मौत हो गई थी। मृतक का नाम प्रशांत साहू उम्र 27 निवासी ग्राम लोहारीडीह है। मृतक का जिला अस्पताल में पीएम कराया गया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने मृतक के साथ मारपीट की थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई है।

इस मामले को लेकर बुधवार को पूरे दिन जिले में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था। कांग्रेस व साहू समाज ने जांच की मांग की थी। मामले को शांत करने के लिए आनन फानन में देर रात खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा को कवर्धा आना पड़ा। उनके साथ रायपुर से पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री की टीम आई थी। देर रात तक चली मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एएसपी विकास कुमार को सस्पेंड करने की घोषणा की।

पुलिस की ऐसी बर्बरता छत्तीसगढ़ में कभी सुनी नहीं गई : भूपेश

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ये आंसू ह्रदय को झकझोर दे रहे हैं...पुलिस की ऐसी बर्बरता छत्तीसगढ़ में कभी सुनी नहीं गई। प्रशांत साहू को पीट-पीट कर मार दिया, उसकी माता जी के शरीर में भी चोट के निशान होने की बात पता चली है। पुलिस की प्रताड़ना के चलते वे चल नहीं पा रही हैं। खून की उल्टियां कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनसे कारागृह में काम करवाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

प्रधान आरक्षक के दोनो बच्चों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी

सुकमा। ग्राम एतकल में 15 सितंबर को जादू-टोना के शक में प्रधान आरक्षक समेत उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। इस हत्याकांड़ में उनके 2 बच्चों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। साय सरकार में कैबिनेट मंत्री और नारायणपुर विधानसभा से विधायक केदार कश्यप ने कहा है कि अब इन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि एतकल गांव की यह घटना बेदह निंदनीय है। समाज कभी भी ऐसे तत्वों को माफ नहीं करेगा, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार में ऐसे अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, इनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केदार कश्यप ने कहा कि इस घटना में जिन बच्चों के माता-पिता की हत्या हुई है, अब उनकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उन्हें पढ़ाया जाएगा, अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। उनकी पूरी परवरिश का जिम्मा सरकार का होगा।

जवानों व ग्रामीणों ने किया नैमेड बाजार स्थल की सफाई

बीजापुर। ग्राम पंचायत नैमेड में कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत नैमेड साप्ताहिक बाजार स्थल में सीआरपीएफ के जवानों एवं ग्रामीणों के संयुक्त सहभागिता से आज गुरूवार को श्रमदान से ब्लैक स्पॉट की सफाई किया गया । विदित हो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार के मार्गदर्शन में जिले के समस्त ग्रामो में गंदे एवं कचरे का ढेर जमा स्थानों (ब्लैक स्पॉट)के चिन्हांकन किया गया है । 02 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत चिन्हित स्थानों को जनभागीदारी से श्रमदान कर सफाई किया जाना है । इसी तारतम्य में जिले के प्रत्येक ग्रामों में स्वच्छता पखवाड़ा चलाकर श्रमदान से सफाई का आयोजन किया जा रहा है, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव एवं स्थानीय दुकानदारों तथा ग्रामीणों ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्रमदान से सफाई कार्यक्रम के उपरांत सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ उपस्थित समस्त ग्रामीणों ने स्वच्छता शपथ लिया ।

कोरिया में पीएमजीएसवाय कार्यालय भवन जर्जर

कोरिया। जिले के बैकुंठपुर स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यालय का भवन जर्जर हालात में है। इस भवन की दीवारों से प्लास्टर लगातार टूट कर गिर रहा है। दीवारों पर गहरी दरारें पड़ गई है। इस वजह से यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कर्मचारियों ने बार-बार भवन की मरम्मत की मांग की है। हर बार जिला प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है। भवन के चारों ओर की स्थिति को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसी भी वक्त गिर सकता है। कर्मचारियों की मानें तो इस जर्जर भवन में काम करना खतरे से खाली नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि मजबूरी में वे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस बारे में जिला कलेक्टर को भी जानकारी दी गई है। उन्होंने जल्द भवन निर्माण की बात कही है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा इस साल बारिश अधिक होने की वजह से कई सरकारी इमारतों की हालत बिगड़ी है। पीएमजीएसवाय कार्यालय के जर्जर भवन के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी।

यात्री ट्रेन और नाइट एक्सप्रेस को 25 सितंबर तक रोका गया

जगदलपुर। जगदलपुर रेलवे स्टेशन से जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के साथ ही नाइट एक्सप्रेस ट्रेन को अभी फिर से रोक दिया गया है। बताया जा है कि रेलवे विभाग की ओर से आने वाले दिनों में फिर से बारिश की संभावना देखी जा रही है, जिसके चलते ईको रेलवे के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। रेलवे विभाग के वाणिज्य प्रबंधन के संदीप ने बताया कि बारिश की संभावना को देखते हुए यात्री ट्रेन और नाइट एक्सप्रेस को एक सितंबर से रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी आने वाले 25 सितंबर तक इन ट्रेनों को आगे जाने नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते दंतेवाड़ा में ही इन ट्रेनों को रोककर रखा गया है।

बाजार में कपड़े खरीदने की जिद्द महिला को पड़ी भारी

रायगढ़। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में मामूली सी बात पर एक पति ने डंडे से पीट-पीटकर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम फूलीकुंडा निवासी पंचराम पंडो (27) ने अपनी पत्नी सुमारी पंडो (25) के साथ लारीपानी साप्ताहिक बाजार गया हुआ था। वहां उसकी पत्नी सुमारी पंडो ने नये कपड़े दिलाने की मांग की है। महिला के पति पंचराम ने मना किया। इसके बाद दोनों के बीच बाजार में ही विवाद हो गया। पंचराम सुमारी को बाजार में ही छोड़कर घर पहुंच गया। काफी देर बाद जब उसकी पत्नी सुमारी घर पहुंची, तब दोनों के बीच फिर से विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि पंचराम ने लकड़ी के डंडे से महिला के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी को लगा था कि संभवत महिला ठीक हो जाएगी, इसलिये उसने महिला के शव को रात भर घर में ही रखा।

कोरिया जिला बिजली के मामले में बनेगा स्मार्ट

■ उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी

कोरिया। कोरिया जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज हो गया है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह अब यहां भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम उपभोक्ताओं से बकाया राशि की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है। स्मार्ट मीटर से विभाग को बकाया वसूली की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

पुराने मीटर के मुकाबले स्मार्ट मीटर की खासियत ये है कि उपभोक्ता को बिजली उपयोग करने से पहले ऑनलाइन रिचार्ज करना होगा। यानी अब पहले बिजली का इस्तेमाल करके बिल भरने की जगह, पहले रिचार्ज करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को अपने खर्च को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही विभाग को भी बेहतर प्रबंधन का लाभ मिलेगा। कोरिया जिले में करीब 40 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। जिनमें से अब तक 800 मीटर लगाए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य समय पर बिलिंग और ऊर्जा खपत को बेहतर ढंग से मॉनिटर करना है। जूनियर इंजीनियर केशव चंद्रा ने कहा हमारे यहां कुल 40 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से 800 मीटर अब तक लगाए जा चुके हैं। पुराने मीटरों में हमें मैन्युअल तरीके से रेडिंग लेनी पड़ती थी, लेकिन अब स्मार्ट मीटर के साथ यह प्रक्रिया स्वचालित हो जाएगी।

पैसा खत्म होने के बाद तुरंत नहीं कटेगी बिजली = स्मार्ट मीटर में यदि उपभोक्ता का रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो बिजली तुरंत नहीं कटेगी। बल्कि उपभोक्ता को तय सीमा में ही बिजली खर्च करनी होगी। निर्धारित सीमा पार करने पर, रिचार्ज न कराने की स्थिति में, बिजली अपने आप डिस्कनेक्ट होगी। इस कदम से ना केवल उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि विभाग को भी राजस्व की वसूली में सहूलियत होगी।

अपहृत बच्ची को बरामद कर मां को किया गया सुपुर्द

दंतेवाड़ा। बचेली थाना क्षेत्र अंर्तगत रेलवे कॉलोनी से छोटी कुंजाम का 18 दिन के बच्चे का अपहरण बुधवार को कर लिया गया। अपहरण में एक महिला शामिल थी, बच्चे की मां छोटी कुंजाम के मुताबिक वह घर में बच्चे को सुलाते हुए पानी लेने के लिए किन्नर अंशु के भरोसे छोड़ कर गई थी, लेकिन जैसे ही वह आई, बच्चे को लेकर किन्नर अंशु फरार हो गया। आस-पास के साथ ही पुलिस ने तत्काल ही टीम बनाते हुए आरोपी की पतासाजी की। आरोपी किन्नर अंशु को 150 किमी दूर जगदलपुर के आड़ावाल से गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसका सहयोग करने वाला एक अन्य युवक साहिल को कोड़ेनार से पुलिस के हिरासत में आने के बाद उसे दंतेवाड़ा ले जाया गया।

प्राप्त जानकारी के किन्नर अंशु ने बच्चे को चुराने के साथ ही अपने पुरुष मित्र साहिल का सहयोग लिया, जहां से दोनों बच्चे को लेकर वहां से भाग निकले, लेकिन युवक को बस्तर पुलिस के साथ ही दंतेवाड़ा पुलिस ने लोकेशन के हिसाब से युवक को कोड़ेनार से गिरफ्तार कर लिया है। आदिवासी महिला छोटी के बच्चे को पहले ही दिन से देखने के बाद अंशु ने प्लान बना लिया था कि वह बच्चे को अपने साथ ले जाकर पाल पोसकर उसे अपने बच्चे जैसे ख्याल रखेगी। इसके लिए उसने अपने युवक मित्र की मदद ली। किन्नर बच्चे को चुराने के बाद जगदलपुर के आड़ावाल में रहने वाली अपनी बहन के घर लेकर गया। बच्चे को बरामद करने के बाद बस्तर पुलिस ने बच्चे का फोटो दंतेवाड़ा एसपी को भेजा। महिला ने अपने बच्चे होने की पुष्टि की। वहीं, बच्चे को आड़ावाल से लाने के बाद सायबर सेल कोतवाली में रखा गया। डॉक्टर की टीम ने बच्चे को दूध पिलाने के साथ ही उसका मेडिकल टेस्ट भी किया, जिससे कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है कि नहीं। बचेली से चोरी हुए बच्चे के बरामद करने के बाद बस्तर पुलिस के साथ ही दंतेवाड़ा पुलिस पोदुम से चोरी हुए बच्चे से भी तार को जोड़ कर उस मामले की भी पूछताछ कर रही है।

दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि 18 सितंबर को बचेली के रेलवे कॉलोनी में छोटी कुंजाम के 18 दिन के बच्चे को दिन में लगभग 11 बजे के आस-पास अपहरण कर लिया गया। बचेली थाना में इसकी सूचना दोपहर साढ़े 12 बजे मिली, परिवार ने बताया कि एक महिला घटनास्थल पर थी, उसके बाद से ही बच्चा और महिला गायब है। उन्होने बताया कि बच्चे के अपहरण की घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई, पूरे दंतेवाड़ा जिले में नाकाबंदी की गई, साथ ही बस्तर जिले में भी नाकाबंदी की गई। सायबर सेल की मदद से दंतेवाड़ा और बस्तर जिले की पुलिस ने 4 घंटे के अंदर बच्चे को शाम 4 बजे आड़ावाल जगदलपुर से सकुशल बरामद कर बच्चे की मां को सुपुर्द कर दिया गया है।

समाचार पचीसा
रायपुर, शुक्रवार 20 सितंबर 2024

संक्षिप्त समाचार

राइस मिलर्स मिले सीएम से, बतायी चावल उद्योग से संबंधित समस्याएं

रायपुर। गुरुवार को मुख्यमंत्री जनदर्शन में

प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय से प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के साथ मुलाकात करते हुए चावल उद्योग से संबंधित विषय पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कोअवगत कराया कि मिलर्स का कस्टम मिलिंग चार्जेस सहित अनेक मद का हजारों करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है जिससे मिलर्स की स्थिति बहुत खराब है। साथ ही कस्टम मिलिंग नीति में भी आमूल चूल सुधार की आवश्यकता है जिससे सरकार किसान व मिलर्स को नुक़सान ना हो। मुख्यमंत्री ने मिलर्स की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा समाधान के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर महासचिव द्वय विजय तायल, प्रमोद जैन, अमर सुलतानिया, संजय गर्ग, विनोद अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, अमित अग्रवाल विवेक छपरिया, टीनू अग्रवाल, अविचल अग्रवाल, दिनेश केडिया, दिनेश अग्रवाल, अतीश अग्रवाल, विनय भूतड़ा सहित प्रदेश भर के राइस मिलर्स प्रतिनिधि उपस्थित थे । मुख्यमंत्री के सचिव बसवा राजू ने भी मिलर्स समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल मार्कफेड में बात कर मिलर्स समस्याओं के समाधान की पहल की। इसके एक दिन पूर्व खाद्य सचिव ऋचा शर्मा से भी मिलकर समस्या का समाधान का अनुरोध किया गया,उन्होने भी सकारात्मक पहल की बात कही।

अजय कुमार सिविल लाइन सीएसपी

रायपुर। गृह विभाग ने 4 ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों की पदस्थापना आदेश जारी किया है और ये सभी सीएसपी पद पर पदस्थ किए गए हैं। गृह (पुलिस) विभाग के संयुक्त सचिव अभिजीत सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में आकाश श्रीमाल परिवीक्षाधीन रायगढ़ से नगर पुलिस अधीक्षक जगदलपुर, अजय कुमार परिवीक्षाधीन बिलासपुर से नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन रायपुर, अजय प्रमोद सबद्रा परिवीक्षाधीन दुर्ग से नगर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर तथा विमल कुमार पाठक परिवीक्षाधीन रायपुर से नगर पुलिस अधीक्षक दर्री कोरबा बनाया गया है।

भाटापारा शाखा नहर के कमांड एरिया में आने वाले खेतों को सिंचाई पानी की दरकार

रायपुर। बीते 10-12 दिनों से प्रभावी बरसात

न होने की वजह से खेतों में खड़ी धान की फसल को एकबार फिर सिंचाई पानी की आवश्यकता है। गंगरेल बांध से छोड़े जा रहे पानी से महानदी मुख्य नहर व मांढर शाखा नहर के कमांड एरिया में आने वाले खेतों को तो सिंचाई पानी मिल रहा है पर भाटापारा शाखा नहर के खेतों को नहीं। प्रभावित ग्रामों के किसानों द्वारा ध्यानाकर्षण कराये जाने पर किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने महानदी जलाशय परियोजना के मुख्य अभियंता कुबेर सिंह गुरुवर को व्हाट्स ऐप के माध्यम से ज्ञापन भेज सिंचाई पानी देने में आ रही दिक्कत को प्राथमिकता के आधार पर दूर करवा इस शाखा नहर में अविलंब पानी छुड़वाने का आग्रह किया है। ज्ञातव्य हो कि गंगरेल बांध से निकले महानदी मुख्य नहर के 101 किलोमीटर से भाटापारा शाखा नहर निकला है जिससे हजारों एकड़ खेतों को सिंचाई पानी मिलता है। बीते दिनों हुये व्यापक वर्षा के पूर्व इस शाखा नहर से सिंचाई पानी मिल रहा था पर बरसात बंद होने के बाद अब जब पानी की आवश्यकता महसूस की जा रही है गंगरेल का पानी इस शाखा नहर में नहीं जा रहा जबकि अभी सामयिक सिंचाई पानी की आवश्यकता है। ज्ञापन में बीते दिनों हुये व्यापक वर्षा के चलते इस शाखा नहर के कहीं पर क्षतिग्रस्त होने की वजह से पानी न दिये जाने की जानकारी मिलने की बात कहते हुये प्राथमिकता के आधार पर त्वरित मरम्मत करवा पानी छुड़वाने का आग्रह किया गया है। इसमें किसी प्रकार दिक्कत होने पर क्षतिग्रस्त हिस्से के पहले पडने वाले क्रास रेग्युलर तक फिलहाल पानी देने व? मरम्मत बाद आगे पानी दिलवाने की मांग की है।

महादेव सट्टा एप पर हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली

रायपुर। महादेव सट्टा एप मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई।

मामले की अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। महादेव सट्टा एप मामले में रायपुर की विशेष अदालत की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। मामले की पूर्व में हुई सुनवाई के बाद आज बचाव पक्ष को प्रति उत्तर प्रस्तुत करना था।

साय की पहल पर राष्ट्रपति से मिलने नक्सल पीड़ित पहुँचे दिल्ली

- 'सुनो नक्सली हमारी बात' के नारे के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर माओवादी हिंसा की वजह से अपाहिज हुए बस्तर के लोग आज बस्तर शांति समिति के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नक्सलियों के लगाए बम से अपाहिज होने वाले एक-दो नहीं बल्कि हजारों में है, जिनका प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली पहुंचे बस्तर के लोग प्रदर्शन के साथ राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात कर अपनी व्यथा बताएंगे।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंजा नक्सली-मनवा माटा (सुनो नक्सली हमारी बात) आंदोलन कर रहे इन नक्सल पीड़ितों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है।

मुख्यमंत्री साय ने बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा से प्रभावित ग्रामीणों से कई बार संवाद किया और उनके दुख-दर्द को नजदीक से समझा। उन्होंने महसूस किया कि इन पीड़ितों की समस्याओं को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता और इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद ही नक्सल पीड़ित आज जंतर मंतर पर अपने अधिकारों और शांति की मांग को सबके सामने रखने का फैसला लिया।

जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान, ग्रामीणों ने माओवादी हिंसा के कारण झेले गए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्टों को व्यक्त किया। वहीं नारायणपुर जिला की रहने वाली राधा सलाम बताती हैं कि बचपन में अपने भाई के साथ आंगनबाड़ी जा रही थी। इस दौरान इमली पेड़ के नीचे नक्सलियों के लगाए बम को बॉल समझकर उसके भाई के उठाए जाने पर फट गया, जिससे दोनों भाई-बहन घायल हो गए।

राधा बताती है कि घटना में लगी चोट से आज उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता है, वहीं दूसरे आंख से कम दिखाई देता है। उसका कहना है कि वह बड़ी होकर आईपीएस बनकर नक्सलियों से बदला लेना चाहती हूं, जिससे दूसरे लोग उसके और उसके भाई की तरह न भुगतें। हम अपनी पीड़ा को बताने के लिए दिल्ली आए हैं, जिससे हमारी पीड़ा को लोग जाने और नक्सलियों की करतूत को समझे।

सुकमा जिले के निवासी महादेव दूधी बताते हैं कि वे दंतेवाड़ा गए थे। वापसी के दौरान बस में विस्फोट हो गया, जिससे उसके एक पैर को काटना पड़ गया। घटना के बाद से जीना मुहाल हो गया है। कोई वजह की चीज नहीं उठा पाता हूं। लेकिन मेरी तरह दूसरों को न भुगतना पड़े इसके लिए मैं (प्रदर्शन करने) दिल्ली में आया हूं। इस आंदोलन के बाद नक्सल पीड़ितों का यह दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। वे बस्तर की वर्तमान स्थिति और नक्सली हिंसा से जुड़े मुद्दों पर गृह मंत्री से चर्चा करेंगे और समाधान के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में बस्तर में शांति बहाली, विकास कार्यों में तेजी लाने और सुरक्षा बलों की उचित तैनाती की मांग की जाएगी।

एक साथ चुनाव से देश को होगा बड़ा लाभः साय

रायपुर। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव (वन नेशन वन इलेक्शन) करने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के इस फैसले के बाद सियासत भी गरमा गई है। विपक्ष राजनीतिक दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। सीएम साय ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिससे देश को बहुत लाभ होगा। समय की बचत होगी और खर्च की बचत होगी। बार-बार चुनाव के कारण आचार संहिता लगने से विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए जा सकें, तो देश को बहुत बड़ा लाभ होगा।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किये गए साप्ताहिक जनदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज जन दर्शन का आयोजन हुआ है। भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। दिव्यांग आए हैं, लोग व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या भी लेकर आए। ज्यादातर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग,स्वेक्षा अनुदान और विभिन्न तरीके समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। जो तत्काल में समाधान किया जा सकते हैं वह हम कर रहे हैं। कुछ दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दिए हैं। आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं, जितना तत्काल में संभव है वह किया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-

राहुल विदेशों में जाकर देश का सम्मान गिराने का कर रहे काम : किरण सिंहदेव

रायपुर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। इस मामले को लेकर अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने राहुल गांधी की बयानबाजी पर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किरण सिंहदेव ने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ राहुल गांधी की बयानबाजी पूरी देश जानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कभी चौकीदार चोर तो कभी मौत का सौदागर कहकर उनकी जाति को लेकर भी टिप्पणियाँ की गई हैं। देश के लोग इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करते। राहुल जी विदेशों में भी जाकर देश के मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं।

इसके अलावा, केंजा नक्सली मनवा माटा के तहत 70 नक्सल प्रभावित लोग दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इस पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा इस मामले पर सतत नजर बनाए हुए हैं। वहां की क्या परिस्थितियां है, किस तरीके से क्या काम हो रहे हैं, इस पर सरकार का फोकस है।

बलौदा बाजार के मामले पर एम के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर किरण सिंहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। पटवारी को जांच और कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए।

रायपुर दक्षिण उप चुनाव के लिए भाजपा में एक दर्जन से अधिक दावेदार सामने आए हैं। इस पर किरण सिंहदेव ने कहा कि भाजपा में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें लोग पार्टी के सामने अपनी दावेदारी कर सकते हैं।

कांग्रेस के नेताओं के कवर्धा जाने पर किरण सिंहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार में थी, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। यदि उस समय प्रदेशवासियों की चिंता की होती, तो आज उनकी स्थिति अलग होती।

रायपुर रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाने की कवायद, तोड़ी गई रेलवे कॉलोनी

सड़क चौड़ीकरण के साथ मल्टी लेवल पार्किंग, रेस्टोरेंट, वर्ल्ड क्लास पैलेस का होगा निर्माण

रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाने के लिए 7 नंबर साइड की रेलवे कॉलोनी तोड़ा जा रहा है। कालोनी में लगे सालों पुराने पेड़ों को भी शिफ्ट किया जाएगा। खाली हुई जमीन पर यात्री सुविधा के हिसाब से भवनों के निर्माण के साथ सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के स्टेशन तक पहुंच पाए।

अमृत भारत मिशन के तहत रायपुर स्टेशन के रि-डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन में तब्दील करने के लिए सबसे पहले गुड़ियारी की तरफ बनी आरपीएफ और लोको पायलट की कॉलोनी के करीब 120 मकानों को तोड़ा गया है। रेलवे यहां वर्ल्ड क्लास पैलेस और रेस्टोरेंट के साथ मल्टीलेवल कार पार्किंग का भी निर्माण करेगा। यही नहीं सड़क बनाई जाएगी, जिसे तेलघानी नाका से भी जोड़ा जाएगा। इससे प्लेटफार्म 5 और 7 आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इसके अलावा जल्द ही प्लेटफार्म 1 की तरफ आरपीएफ पुलिस थाना, पार्सल कार्यालय और आरक्षण काउंटर को भी तोड़ा जाएगा। आरपीएफ कॉलोनी वाले परिसर के खाली होने पर फाफाडीह तक एक्सप्रेस-वे का विस्तार हो जाएगा। यहीं पर पार्किंग बिल्डिंग बनाई जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेस-वे सड़क घूमकर स्टेशन से जुड़ी हुई है।

इसके अलावा आज जहां मुख्य रिजर्वेशन टिकट का ऑफिस है, वहां एक मल्टीस्टोरी पार्किंग बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें पार्सल कार्यालय भी होगा। रायपुर स्टेशन को सिटी सेंटर की तरह बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 470 करोड़ की मंजूरी दी है। वर्तमान में अभी जो प्लेटफार्म है, उसकी चौड़ाई डेढ़ गुना तक बढ़ जाएगी।

रेलवे अफसरों के अनुसार, कॉलोनी में आधा दर्जन से ज्यादा पेड़ ऐसे हैं, जो करीब 50 साल पुराने हैं। इन पेड़ों को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी, ताकि पेड़ सूखे खराब न हो। पेड़ों के शिफ्ट होने के बाद तोड़फोड़ के काम में और तेजी लाई जाएगी।

इस पूरे मामले में रेलवे के सीनियर छ्ष्टरूअवधेश कुमार त्रिवेदी का कहना है कि स्टेशन का निर्माण आने वाले 40 साल को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। लगभग 36 मीटर एफोब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। वहां पर नवीन निर्माण भी कराया जा रहे हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग, नवीन रेस्टोरेंट, कमर्शियल प्लेस होंगे, रेलवे स्टाफ, टीटीई के लिए वर्ल्ड क्लास फैसलिटी होगी।

आपस में भिड़े ब्लॉक अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के नेता

डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ ब्लॉक कांग्रेस की आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है, जहां वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के दो गुटों के बीच मंच पर ही मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजयराज सिंह और युवा कांग्रेस के नेता संदीप सिंह गहरवार एक-दूसरे से मारपीट करते दिख रहे हैं। मामला डोंगरगढ़ में गणेश झांकी विसर्जन के दौरान का है। डोंगरगढ़ के गोल बाजार में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान झांकियों को पुरस्कार देने के लिए कांग्रेस की ओर से मंच बनाया गया था। बताया जा रहा है कि मंच पर लगे बैनर में फोटो नहीं छापने से नाराज जिले के बड़े कांग्रेसी नेता नवाज़ ख़ान के करीबी माने जाने वाले युवा कांग्रेस नेता संदीप सिंह व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय राज चौहान आपस में उलझ गए। दरअसल, पिछले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से डोंगरगढ़ कांग्रेस में आंतरिक कलह देखने को मिल रही है, जो गणेश विसर्जन के दौरान खुलेआम भरे मंच पर भी दिखाई दी। माना जा रहा है कि आगामी निकाय चुनाव में इसका असर और भी गहराएगा। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से शहर में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है।

आज से दुर्ग-विशाखापटनम वंदेभारत नियमित रुप से पटरी पर

रायपुर। गाड़ी संख्या 20829/20830 दुर्ग-विशाखापट्टनम-दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस 20 सितंबर से गुरुवार को छोड़कर सुबह 5.45 पर दुर्ग से नियमित रूप से पटरियों पर दौडने् लगेगी इस ट्रेन में आरक्षण की शुरुआत हो चुकी है। रेलवे ने दुर्ग-विशाखापट्टनम-दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया और समय सारिणी जारी कर दी है।

वंदे भारत एक्सप्रेस अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे (99 मील प्रति घंटे) तक की गति प्राप्त कर सकती है, दुर्ग ङ्क विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, जिससे प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय कम करने में मदद मिलती है। आराम॰ वंदे भारत एक्सप्रेस में पर्याप्त पैर रखने की जगह के साथ रिक्लाइनिंग सीटें हैं। सुरक्षा: वंदे भारत एक्सप्रेस में कई सुरक्षा विशेषताएं हैं, जिनमें स्वचालित दरवाजे, स्मोक अलार्म, सीसीटीवी कैमरे, बायो-वैक्यूम शौचालय और कवच सिग्नलिंग तकनीक शामिल हैं।

वंदे भारत एक्सप्रेस में स्वचालित प्लग दरवाजे और ऑनबोर्ड वाई-फाई की सुविधा है। सुविधाएं:वंदे भारत एक्सप्रेस में आपदा रोशनी, अग्नि बचाव केबल और वेंटिलेशन सहित उन्नत सुविधाएं दी गई हैं। एयर कंडीशनिंग: वंदे भारत एक्सप्रेस में बैक्टीरिया मुक्त एयर कंडीशनिंग प्रणाली है। बाढ़ सुरक्षा: वंदे भारत एक्सप्रेस में विद्युत उपकरणों के लिए बाढ़ से अधिक सुरक्षा की व्यवस्था है।

दिनांक 20 सितम्बर से गाड़ी संख्या 20829/20830 दुर्ग-विशाखापट्टणम-दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा सप्ताह में छह दिन (गुरुवार को छोड़कर) दोनों छोर से संचालित की जाएगी। इस खंड में चलने वाली अन्य ट्रेनें दुर्ग से विशाखापट्टणम के बीच की दूरी को लगभग 11 घंटे में तय करती है। दुर्ग- विशाखापट्टणम वंदे भारत दुर्ग एवं विशाखापट्टणम के बीच की दूरी को 8 घंटे में तय करेगी, जिससे लगभग 3 घंटे समय की बचत होगी। यह ट्रेन दुर्ग और विशाखापट्टणम जैसे दो प्रमुख शहरों को जोड़ती है, जो पर्यटन और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साथ चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी यह ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

गाड़ी संख्या 20829 / 20830 दुर्ग - विशाखापट्टनम - दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस 20 सितंबर 2024 से यात्रियों के लिए यात्रा के लिए उपलब्ध रहेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इस गाड़ी में आरक्षण की सुविधा शुरुवात कर दी गई है। यात्रीगण अपनी सुविधा के अनुसार से एग्जीक्यूटिव क्लास एवं चेयर कार में अपना आरक्षण कर सकते हैं। इस गाड़ी का ठहराव रायपुर, महासमुंद, खरीयार रोड, कांटाबांजी, टीटलागढ़, केसिंगा, रायगड़ा, पार्वतीपुरम, विजयनगरम रहेगा। इस ट्रेन में 16 कोच शामिल हैं। 20 सितंबर से ट्रेन नं. 20829/20830 दुर्ग- विशाखापट्टणम -दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने नियमित समय-सारणी के अनुसार चलेगी। गाड़ी संख्या 20829 दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग से 5॰45 बजे रवाना होकर 6.13 बजे रायपुर 6.53 बजे महासमुंद, 7.28 बजे खरियार रोड, 8.13 बजे कांटाबाजी, 8.46 बजे टिटलागढ़ 8.55 बजे केसिंगा, 11:00 बजे रायगड़ा, 11:30 बजे पर्वतीपुरम 12.35 बजे विजयनगरम एवं 12:45 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 20830 विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से 14.50 बजे रवाना होकर 15.33 पर विजयनगरम, 16.36 बजे पर्वतीपुरम, 17.13 बजे रायगड़ा, 18.50 बजे केसिंगा, 19॰05 बजे टिटलागढ़, 19.35 बजे कंटबंजी, 20.20 बजे खरियार रोड, 21.00 बजे महासमुंद, 22.19 बजे रायपुर 22.50 बजे दुर्ग पहुंचेगी।

5 लोगों की हत्या की जांच करने कांग्रेस ने बनाई समिति

मंत्री श्यामबिहारी बोले- घटनाएं रोकने सबको मिलकर समाज में लाना होगा जागरूकता

रायपुर। जादू-टोना के शक में सुकमा जिले में हुई 5 लोगों की हत्या मामले में सियासत भी तेज हो गई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा, हमारे पास जांच करने के लिए पूरी प्रशासनिक टीम है।

कांग्रेस अपनी जांच टीम बनाई है। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं को केवल सरकार के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज में जागरूकता लाना होगा।

मंत्री जायसवाल ने कहा, हमने हेल्थ सेक्टर को देखते हुए बस्तर जैसे क्षेत्र में निचले स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में इस तरह की सामाजिक कुरीतियां समाप्त हो, जादू टोना के प्रति जो आज भी लोगों पर मानसिकता फैली हुई है वह समाप्त होनी चाहिए।

रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस के समिति गठन पर श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस प्रकार की टीम पहले भी बनाती आई है। अभी भी बना रही है। इसका क्या रिजल्ट आया, ये सबके सामने है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समय भी टीम बनाई थी। ये लोग कुछ भी कर लें, इनके 5 साल के कार्यकाल को जनता अच्छे से समझती है। आज उसी का परिणाम है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबसे पीछे रहे हैं।

दक्षिण रायपुर उपचुनाव की तैयारी को लेकर मंत्री श्यामबिहारी ने कहा, समय सीमा तय तो चुनाव आयुक्त करेगा, परंतु जब भी चुनाव होगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव का निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति करता है। जब कोई मजबूत पार्टी होता है तो कई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के योग्य है। जो भी कैंडिडेट तय करना होता है वह केंद्रीय नेतृत्व तय करता है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-सुकमा (छ.ग.)
Phone&Fax-07864284013, Email-deo-sukama.cg@nic.in

क्रमांक / 2556/ सा0निर्वा./स्था. वित्त/2024-25 सुकमा, दिनांक 05/09/2024

// निविदा सूचना //

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश एवं मापदण्ड अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-90/कोन्टा के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों, बी.एल.ओ. वर्किंग कॉफी एवं मतदाता पर्ची का मुद्रण का कार्य इच्छुक एवं योग्य फर्मों से निविदा आमंत्रित किया जाता है इच्छुक निविदाकार निविदा पत्रक कार्यालयीन अवधि में संयुक्त जिला कार्यालय सुकमा के प्रथम तक कक्ष क्र.-50 में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय सुकमा से निविदा शुल्क रु. 500.00 (रू. पांच सौ मात्र) नगद जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा आमंत्रित की जाने हेतु विविरण निम्नानुसार है:-

1. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि -25-09-2024 (बुधवार) को दोपहर 01.00 बजे तक।
2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि -25-09-2024 (बुधवार) को दोपहर 03.00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि -25-09-2024 (बुधवार) को सायं 04.00 बजे तक।

फर्मों से प्राप्त निविदा पत्र, गठित निविदा समिति द्वारा संयुक्त जिला कार्यालय भवन सुकमा के प्रथम तक कक्ष क्र.-50 में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय सुकमा में दिनांक 25/09/2024 को समय सायं 04.00 बजे निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

(कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-सुकमा (छ.ग.)

जी-242502587/4

अखिलेश यादव से किनारा करती कांग्रेस और राहुल गांधी

अजय कुमार

कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर नजरिया बदलता जा रहा है। अब कांग्रेस और राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वह अहमियत नहीं दे रही है जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय दी थी। वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे के प्रति जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे यही लगता है कि जल्द ही कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का दौर खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं पिछले कुछ समय से जिस तरह से अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमों मायावती के बीच दूरियां बढ़ी हैं उससे भी अखिलेश यादव अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। यूपी की दस विधान सभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई तो उसके लिये आगे के लिये अपनी साख बचाना मुश्किल हो जायेगा। वैसे भी मायावती ने उप चुनाव में बसपा के भी प्रत्याशी उतारने की बात कहकर अखिलेश की धड़कने बढ़ा ही रखी हैं। बात कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती खाई की कि जाये तो पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी एक परिपक्त नेता की तरह आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना गोल निर्धारित कर लिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना और मुस्लिमों को लुभाने में राहुल गांधी हिन्दुओं पर आक्रमक होने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं।जिसका उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में फायदा होता भी दिख रहा है। उधर, पहले मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं देकर यह संदेश दे दिया है कि उसके लिये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर मायने नहीं रखती है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बैसाखी के सहारे सपा महाराष्ट्र मे अपनी ताकत बढ़ाने की जो कोशिश कर रही थी, उस पर भी पानी फिरता दिख रहा हैं। वैसे सपा की महाराष्ट्र यूनिट ने 12 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, विधायक इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज और प्रभारी बनाया गया है। कुल मिलाकर दूसरे प्रदेशों में अपनी जड़े मजबूत करने का सपना देख रहे अखिलेश यादव को कांग्रेस से लगातार झटके पर झटका ही मिल रहा है। महाराष्ट्र इस कड़ी का नया हिस्सा बन गया है। सपा के पास विकल्प की बात की जाये तो वह फिलहाल सिर्फ यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब दे सकती है। यूपी में सपा की स्थिति कांग्रेस से कहीं अधिक मजबूत है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीतने वाली सपा दूसरे राज्यों की विधानसभाओं में खाता खोलकर राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करना चाहती है। दूसरे राज्यों में सपा का संगठन उतना प्रभावी नहीं है, जितना उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में सपा ने कांग्रेस के सहारे चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कई बार की है। पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी। उस चुनाव में कांग्रेस के सपा से गठबंधन न करने पर सपा ने अपने दम पर 22 प्रत्याशी उतारे थे। सपा का खाता तो नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस को कुछ सीटों पर नुकसान जरूर हुआ। इसी तरह से हरियाणा की मुस्लिम और यादव बहुल 12 विधानसभा सीटों पर सपा ने कांग्रेस से गठबंधन करने का प्रयास किया था। बात पांच और फिर तीन सीट पर आकर टिक गई थी। कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की तो एक भी सीट सपा के लिए नहीं छोड़ा। हालांकि, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'बात सीट की नहीं, जीत की है' कहकर गठबंधन धर्म निभाने के लिए त्याग करने के संकेत दे दिए हैं। हरियाणा के सपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी भी कहते हैं कि तीन सीटों को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को संदेश भेजा था। संगठन ने पूरी तैयारी की, लेकिन कांग्रेस इससे पीछे हट गई। वहीं, दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर की 20 सीटों पर सपा ने कांग्रेस गठबंधन नहीं होने पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और सपा आमने-आमने है।

'एक देश एक चुनाव' अमृतकाल की अमृत उपलब्धि बने

ललित गर्ग

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 'एक देश एक चुनाव' के अपने चुनौतीपूर्ण संकल्प को लागू करने की बात कहकर राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती एवं चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं कम खर्चीला बनाने के लिये 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा होती रही है। इसको लेकर भाजपा जिस तरह बेझिझक होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा कि केंद्र को सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा। दो बड़े दलों में से एक जेडीयू ने मोदी के 'एक देश एक चुनाव' वाले इरादे पर सहमति जता दी है। कहा गया कि राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के भीतर इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लागू कराने को लेकर आशावादी है और उसके इस आशावाद में देश को एक नई दिशा मिल सकेगी। भारत की वर्तमान चुनावी प्रणाली में निहित कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक संभावित समाधान के रूप में उभरी है। शासन के सभी स्तरों- पंचायत, नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय- में एक साथ चुनाव कराने से लागत (खर्च)-प्रभावशीलता और प्रशासनिक दक्षता से लेकर बेहतर शासन और नीति निरंतरता तक कई लाभ मिल सकते हैं। यह नये भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को आकार देने का मुख्य आधार बन सकता है एवं आजादी के अमृतकाल की एक अमृत उपलब्धि बनकर सामने आ सकता है।

भले ही स्पष्ट बहुमत के अभाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की तीसरी पारी में बदलावकारी फैसले लेना उतना सहज नहीं रह गया है, जितना पहली-दूसरी पारी में नजर आता था। लेकिन भाजपा की सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि अपने चुनावी वायदों एवं विकासमूलक कार्ययोजनाओं को लागू न कर सके। नरेन्द्र मोदी जैसा साहसी एवं करिश्माई नेतृत्व है तो उसके द्वारा देशहित की योजनाओं में आने वाले अवरोध वह दूर कर ही लेंगे। एक दशक की विकासमूलक कार्यशैली के बाद अब भी भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को अंजाम तक

पहुंचाने में जुटी है। भले ही भाजपा-सरकार कई मुद्दों पर यू टर्न लेते हुए भी नजर आई। बहरहाल, लोकसभा में पहले के मुकाबले कमजोर स्थिति होने के बावजूद खुद को साहसिक निर्णय लेने वाली पार्टी के रूप में एक बार फिर अपने एक मुख्य एजेंडे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को आकार देने के लिये तत्पर हो गयी है। इसके लिए सरकार ने पक्ष-विपक्ष के सभी नेताओं से एक साथ आने का अनुरोध किया था। निस्संदेह, एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये भाजपा द्वारा नई पहल किए जाने के निहितार्थ राजनीति से ज्यादा राष्ट्रहित में है।

निश्चिय ही 'एक देश एक चुनाव' की योजना को लागू करना राजग के लिये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस बार विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत भी है और एकजुट भी है। इसमें दो राय नहीं कि यह बात तार्किक है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रयास शासन में सुनिश्चितता लाएगा। वहीं बार-बार के चुनाव खर्चीले होते हैं। दूसरे राज्य-दर-राज्य लंबी आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य भी बाधित होते हैं। साथ ही साथ शासन-प्रशासन व सुरक्षा बलों की ऊर्जा के क्षय के अलावा जनशक्ति का अनावश्यक व्यय होता है। विगत लोकसभा चुनावों में कुल सरकारी खर्च 6600 करोड़ रुपये आया था जो भारत जैसे विविधतापूर्ण विशाल देश को देखते हुए भले ही जायज कहा जाये, लेकिन बार-बार होने वाले चुनावों से होने वाले ऐसे भारी-भरकम खर्चे देश की अर्थ-व्यवस्था पर बोझ तो डालते ही है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ भी महंगी होती चुनाव व्यवस्था है क्योंकि जब करोड़ों रुपये खर्च करके कोई विधानसभा या लोकसभा का प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनेगा तो वह विजयी होने के बाद सबसे पहले अपने भारी खर्च की भरपाई करने की कोशिश करेगा। अत: असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करने पर सभी राजनैतिक दलों में एक सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन पक्ष एवं विपक्ष को अपने राजनीतिक हितों की बजाय देशहित को सामने रखकर इस मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव के लिये एक साथ चुनावी मशीनरी तथा सुरक्षा बलों की उपलब्धता के यक्ष प्रश्न को भी सामने रखकर इस पर सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत हमेशा से राजनीतिक विचारधाराओं, विविध संस्कृतियों और विशाल आबादी का मिश्रण रहा है। हर गुजरते चुनाव चक्र के साथ, राष्ट्र लोकतांत्रिक उत्साह का महाकुंभ देखता है, जहाँ लाखों लोग अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हालाँकि, इस जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच, विभिन्न स्तरों-स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय-पर चुनावों के समन्वय को लेकर बहस ने हाल के वर्षों में काफी जोर पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक दशक के शासन एवं पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किए गए अपने संबोधन में 'एक देश, एक चुनाव' की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों से लाल किले से और राष्ट्रीय तिरंगे को साक्षी मानकर राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जारी चुनाव घोषणापत्र में उसने 'एक देश, एक चुनाव' को प्रमुख वादों के रूप में शामिल किया था।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओं के साथ आम लोगो एवं न्यायविदों के विचार आमंत्रित किये। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। इसके अलावा, विधि आयोग भी 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करते हुए सभी राजनैतिक दलों के सामने निजी हित एवं चुनाव जीतने का गणित सामने आ जाता है। भारत की असली विडम्बना यही है। जब भी सरकारी खर्चे से चुनाव कराने की बात होती है तो इस राह को अव्यावहारिक बता दिया जाता है। जबकि जर्मनी जैसे लोकतन्त्र में यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव एक साथ प्रत्येक पाँच वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं, जबकि नगर निकाय चुनाव प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी कौंसिल और स्थानीय निकायों/नगर निकाय सभाओं के चुनाव एक निश्चित तिथि, यानी हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किये जाते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया कि प्रथम चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष मई माह के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा।

जब दुनिया के अनेक देशों में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की परम्परा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है तो भारत में इसे लागू करने में इतने किन्तु-परन्तु क्यों है? देश में इसे लागू करने से सरकार कुछ-कुछ समय बाद चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन यानी विकास योजना पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे समय एवं संसाधनों की भी बचत होगी। एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई मत डालना आसान हो जाएगा। इन सब स्थितियों के साथ-साथ एक साथ चुनाव कराये जाने पर क्षेत्रीय पार्टियों को होने वाले नुकसान एवं अन्य स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि एक आदर्श एवं सशक्त लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के लिये समान अवसर उपलब्ध होना भी जरूरी है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रमाण-संग्रहाध्यायः (दूसरा अध्याय)

गतांक से आगे...

सायणीय अर्थभाष्य-उपोद्घात- (41) यथा स्कान्दे कमलालयखण्डे आथर्वणमन्त्राणां जपमात्रेणाभिमतफलसाधनत्वम् उक्तम्। यस्त-गाथर्वणान् मन्त्रान् जपेच्छद्धासमन्वितः। तेषा-मर्थोद्भवं कृत्स्नं फलं प्राप्नोति सो ध्रुवम्।। इति।। (अथर्व सायणभाष्य पृष्ठ 5)

अर्थात्- स्कन्दपुराण कमलालय (कुमारिक) खण्ड में अथर्व मन्त्रों के जपमात्र से इच्छित फल की प्राप्ति होती है ऐसा कहा है, यथा यज्ञादि में जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक अथर्व मन्त्रों का जाप करेगा उसे निश्चित ही अर्थसहित वेदपाठ का पूर्ण फल होगा।

121/788 (42) पौरोहित्यं च अथर्वविदैव कार्यम्। तत्कर्तृकाणां कर्मणां राजाभिषेकादीनां तत्रैव विस्तरेण प्रति-पादितत्वात्। तथा च विष्णुपुराणे पौरोहित्यं शान्तिकपौष्टिकानि राज्ञामथर्ववेदेन कारयेद् ब्रह्मत्वं च। (अथर्व-सायणभाष्य पृष्ठ 6)

अर्थात्- पुरोहित का कार्य अथर्ववेदज्ञ से ही करवाना चाहिए। क्योंकि राज्याभिषेक आदि पुरोहित-कर्तृक कर्मों का उल्लेख विस्तारपूर्वक अथर्व में ही है। जैसा कि विष्णुपुराण में कहा है- राजाओं के यहां शान्तिक पौष्टिक श्रादि पुरोहित सम्बन्धी कार्य अथर्ववेद द्वारा कराने चाहियें। तथा यज्ञादि में ब्रह्मत्व भी इस वेद से होता है।

मत्स्यपुराशा- (43) %पुरोहितं तथाथर्वमन्त्रब्राह्मणहारगम्। इति। (अथर्व सायणभाष्य पृष्ठ 7) अर्थात् - मत्स्यपुराण में लिखा है अथर्ववेद के मन्त्रब्राह्मणात्मक दोनों भागों का पारङ्गत पुरोहित होना चाहिए ।

मार्कण्डेयपुराण- (44) अभिषिक्तोऽथर्वमन्त्रैर्महीं भुक्ते ससागराम्। (अथर्व सायणभाष्य पृष्ठ 8) अर्थात् - मार्कण्डेय पुराण में लिखा है-अथर्वमन्त्रों द्वारा अभिषक्त होकर वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का राजा हुआ। **क्रमशः...**

रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) सेवा और समर्पण की मिसाल है। यह देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा एवं देश- विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखता है। रेल के अधीन इस बल को दोषियों की गिरफ्तारी, जांच - पड़ताल करने एवं अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार है। हर साल रेलवे पुलिस बल का स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1985 में रेलवे पुलिस बल को केंद्रीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया था। 29 अगस्त 1957 को संसद द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम बनाया गया, जिसमें सुरक्षा बल का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया। 1965 में इसे ''रेलवे सुरक्षा विशेष बल'' नाम दिया गया। 1966 में

आरपीएफ को रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी अधिकार) अधिनियम बनाकर रेलवे संपत्ति के बेहतर संरक्षण के लिए कानूनी अधिकार दिए गए हैं।

भारतीय रेल जितनी विस्तृत है, उसकी सुरक्षा का दायरा भी उतना ही बड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) इस काम को बड़ी मुस्तैदी से करता है।

रेलवे सुरक्षा बल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है यह सुरक्षा बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन होता है। रेलवे सुरक्षा बलों की तादाद 65000 के लगभग है। रेलवे सुरक्षा बल का मुखिया डाइरेक्टर जनरल होता है जो कि प्राय: भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होते हैं।

रेलवे सुरक्षा बल रेल यात्रियों, रेलवे सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ साथ रेलवे क्षेत्र में अनाथ बच्चों को भी सहायता प्रदान करता है तथा उनके पुनर्स्थापना की भी व्यवस्था करता है। साथ ही तथा इतना ही नहीं भारतीय रेलवे की क्षमता एवं छवि को बनाने के लिए भारतीय रेलवे के अन्य विभागों की भी आवश्यकतानुसार सहायता करता है यह अपराधियों के धर-पकड़ में स्थानीय पुलिस की भी मदद करता है एक प्रकार से यह सरकार, रेलवे विभाग, स्थानीय पुलिस तथा जनता के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। इसकी उत्पत्ति निगरानी करने एवं रक्षा करने के उद्देश्य के साथ रेलवे प्रशासन द्वारा की गई थी बाद में इसे रेलवे सुरक्षा बल का नाम दिया गया और इसे बिना वारेण्ट के गिरफ्तार करने तथा रेलवेसम्पत्तियों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया।

आरपीएफ पूरी निष्ठा और सेवा भाव से अपना कार्य करती है। स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर, पौधरोपण और परेड का आयोजन होता है।

देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का बड़ा ही योगदान रहा यही वजह रही की माल की ढुलाई के लिए अंग्रेजों ने रेलवे की सहायता ली पर समय के साथ साथ रेलवे सम्पत्तियों की चोरी और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा बल की स्थापना की जरूरत महसूस की गई फल स्वरूप इसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 में एक कानून बना कर की गई।

खामेनेई के भारत पर आरोप के पीछे की मंशा क्या?

अजय बोकिल

ईरान और भारत के बीच अच्छे रिश्तों के बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई द्वारा मुसलमानों को प्रताड़ित किए जाने वाले देशों की सूची में भारत का नाम लेना सभी के लिए चौंकाने वाला है, वह भी तब कि जब ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए कठोर आर्थिक प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर भारत ने ईरान से व्यापारिक रिश्ते न सिर्फ कायम रखे, बल्कि उन्हें मजबूती दी है। ज्यादा हैरानी की बात है कि कथित मुस्लिम प्रताड़ना वाले देशों में उन्होंने उस चीन का नाम नहीं लिया है, जहां उइगुर मुसलमानों को नमाज पढ़ने और रोजे रखने तक की इजाजत नहीं है और जिनका बेखौफ चीनीकरण किया जा रहा है। तो क्या खामेनेई का भारत पर आरोप लगाना भारत के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ने की सोची समझी चाल है, भारत के साथ ईरान की एहसान फरामोशी है या फिर ऐसे बयान देकर खुद को दुनिया में मुसलमानों का एकमात्र मुसलमानों का नेता साबित करने की मंशा है?

गौरतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने पैगम्बर मोहम्मद के जन्म दिन पर आरोप लगाया कि भारत में मुस्लिम पीड़ित हैं। खामेनेई ने 16 सितंबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत को उन देशों में शामिल किया, जहां मुस्लिमों को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। इस पर भारतीय भारतीय विदेश मंत्रालय ने तत्काल कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम खामेनेई के बयान की निंदा करते हैं। यह अस्वीकार्य और पूरी तरह से भ्रामक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों के मामले पर कमेंट करने वाले देशों को पहले अपने रिकॉर्ड को देखना चाहिए। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान को 'एक्स' पर शेयर भी किया। इसके पूर्व एक कमेंट में खामेनेई ने लिखा था- दुनिया के मुस्लिमों को भारत, गाजा और म्यांमार में रह रहे मुस्लिमों की तकलीफ से अनजान नहीं रहना चाहिए। अगर आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ

सकते तो आप मुस्लिम नहीं हैं। खामेनेई ने आरोप लगाया कि इस्लाम के दुश्मन मुस्लमानों में फूट डालते आए हैं। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि जब खामेनेई भारतीय मुसलमानों के खैरख्वाह बने हैं। खामेनेई ने 2020 के दिल्ली दंगों के बाद कहा था कि भारत में मुस्लिमों का नरसंहार हुआ है। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार को मुस्लिमों का नरसंहार बंद करना होगा, नहीं तो इस्लामी दुनिया उनका साथ छोड़ देगी। कश्मीर के मुद्दे पर भी खामेनेई कई बार विवादित बयान देते आए हैं। साल 2017 में खामेनेई ने कश्मीर की तुलना गाजा, यमन और बहरीन से की थी।

5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के कुछ दिन बाद खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा था- हम कश्मीर में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। खामेनेई 1980 में जम्मू-कश्मीर का दौरा भी कर चुके हैं। कश्मीर मामले में ईरान का रवैया भारत विरोधी ही रहता आया है। इसी साल यानी 2024 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अप्रैल में अपने पहले पाकिस्तान दौरे पर गए थे तो दोनों देशों के साझा बयान में कश्मीर का जिक्र था। इस पर भारत ने ईरान के सामने आपत्ति जताई थी। इन सबके बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में खामेनेई के बयानों और ईरान के रवैये को आड़े नहीं आने दिया और ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए आपसी सम्बन्ध बेहतर बनाने पर ही जोर दिया है। जहां तक भारत में मुसलमानों की कथित प्रताड़ना की बात है तो यह धारणा तथ्यों से विपरीत है। स्थानीय कारणों से होने वाले विवाद अथवा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को देश के 24 करोड़ मुसलमानों की प्रताड़ना से जोड़ना एक सोची समझी और दुर्भावनापूर्ण रणनीति है।

गाजा में जो इजराइल कर रहा है, या म्यानमार की सैनिक सरकार वहां रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रही है, उसके कारण अलग हैं। वैसे भी फिलीस्तीन मामले में भारत दो राष्ट्र नीति का समर्थक रहा है। हम चाहते हैं कि फिलीस्तीन और इजराइल दोनो राष्ट्र रहें। इजराइल और ईरान के बीच कट्टर दुश्मनी है। इसका कारण इजराइल को अमेरिका का अंध समर्थन और ईरान की परमाणु शक्ति बनने की अदम्य इच्छा। इससे भी बड़ा कारण ईरान की इस्लामिक जगत का नया लीडर बनने की तमन्ना है। वैसे भी आज दुनिया के 57 मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करने की चार देशों में होड़ मची है। ये हैं - सउदी अरब, जो खुद को मुसलमानों का स्वाभावित नेता मानता है। दूसरा है, तुर्की जो हाल के वर्षों में मुस्लिम कट्टरपंथ की तरफ झुका है।

तीसरा है मलेशिया, जिसने सउदी अरब की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्लिम देशो को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। अब इसमें ईरान का नाम भी शामिल हो गया है। इन चारो देशों में भी ईरान अकेला शिया बहुल देश है। पिछले दिनों चीन ने मध्यस्थता कर ईरान और सुन्नी बहुत सउदी अरब के बीच समझौता कराके दुनिया को चौंकाया था। हालांकि, इससे दोनो चिर प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच रिश्ते बहुत मधुर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। खामेनेई के बयान के पीछे भारत और सउदी अरब के मधुर रिश्ते भी कारण हो सकते हैं। खामेनेई का भारतीय अल्पसंख्यक मुस्लिमों के प्रति प्रेम सही भी हो सकता था, अगर खुद ईरान में अल्पसंख्यकों के साथ मानवीय व्यवहार होता। मुस्लिम भाईचारे के तमाम दावों के बाद जमीनी हकीकत यह है कि आज दुनिया में सर्वाधिक मारकाट मुस्लिम देशों और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के बीच ही हो रही है। हालांकि, इसमें गजा में मारे जाने वाले मुसलमानों की संख्या शामिल नहीं है। जहां हमास-इजराइल युद्ध में 50 हजार से ज्यादा मुसलमान मारे जा चुके हैं। खुद ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नियों, बहाइयों, पारसियों और कुर्दों के साथ क्या व्यवहार होता है, यह दुनिया जानती है।

पिछले दिनो ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की थी, वह सुन्नी बलूची संगठनों के खिलाफ ही थी। यही हाल सुन्नी कुर्दों का भी है। ईरान सरकार उन्हें सख्ती से कुचलती रही है। इधर भारत में मोदी सरकार पर आरोप है कि उसके राज में देश में मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश की जा रही है। इसमे आंशिक सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसकी तुलना गजा, म्यानमार जैसे देशों से करना यही साबित करता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए मुसलमान होने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। गनीमत है कि अयातुल्लाह खामेनेई और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा यदा कदा दिए जाने वाले भारत विरोधी और मुस्लिम समर्थक बयानों के बावजूद दोनो देशों के कूटनीतिक व व्यापारिक रिश्तों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है। ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम के कारण कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हैं। इसके बाद भी भारतीय नेता ईरान का दौरा करते रहे हैं। हाल में दोनो देशों के बीच हुए एक अहम समझौते के तहत ईरान के चाबहार स्थित शाहित बहिश्ती बंदरगाह का संचालन अगले 10 साल के लिए भारत ही करेगा। जिसका लाभ अफगानिस्तान को भी होगा और जिसे पाकिस्तान के ग्वादर में चीन द्वारा विकसित किए जा रहे बंदरगाह का जवाब माना जा रहा है। भारत ईरान से मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। जबकि ईरान भारत से बासमती चावल व अन्य वस्तुएं आयात करता है। बहरहाल खामेनेई के खुले भारत विरोध के बाद ईरान के साथ हमारे रिश्ते क्या दिशा लेते हैं, यह देखने की बात है।

आज का इतिहास

1839 नीदललैंड के पहले रेल मार्ग एम्सटरडम से हार्लेम का उद्घाटन हुआ।
1848 विज्ञान की प्रगति के लिए अमेरिकन एसोसिएशन बनाया गया।
1867 ऑस्ट्रिया में हंग्री के विलय के पश्चात फ्रांसवा जोज़फ औपचारिक रुप से ऑस्ट्रिया हंग्री के सम्राट बने।
1881 चेस्टर ए आर्थर ने 21 वे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।
1884 सैन फ्रांसिस्को में इच्ल राइट्स पार्टी का गठन किया गया।
1906 उस समय का सबसे बड़ा और सबसे तेज जहाज इंतेहाई दुनिया का महासागर लाइनर आरएमएस मूरतनिया लॉन्च किया गया था।
1925 हेरोल्ड लॉयड कॉमेडी फिल्म द फ्रेशमैन को परदे पर दिखाया गया।
1943 द्वितीय विश्व युद्ध-ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने न्यू गिनी में काईपिट की लड़ाई में शाही जापानी सैनिकों को हराया।
1946 पहला कान फिल्म फेस्टिवल कान्स के रिसॉर्ट शहर में खोला गया। यह एक वार्षिक उत्सव होगा जो फ्रेंच रिवेरा पर होगा।
1954 आईबीएएम द्वारा विकसित फोरट्रान भाषा के पहले प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चलाया गया।
1970 रूसी प्रोब ने चांद के सतह से कुछ चट्टानें इकट्ठा की।
1971 हरिकेन इरेन (उपग्रह चित्र।) ने निकारागुआटो को सफलतापूर्वक अटलांटिक महासागर से प्रशांत में पार करने वाला पहला ज्ञात उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया।
1973 दुनिया के मशहूर बैटल ऑफ सस्केस में बिली जीन किंग ने जीत दर्ज की।
1977 पश्चिमी सोवियत संघ, फिनलैंड और डेनमार्क में अज्ञात प्रकृति के खगोलीय दृश्यों की एक श्रृंखला देखी गई।
1977 पश्चिमी सोवियत संघ, फिनलैंड और डेनमार्क में अज्ञात प्रकृति की खगोलीय घटनाओं की एक श्रृंखला देखी गई।
1984 द कॉस्बी शो, जो तीन अमेरिकी में से एक बन गया, जो लगातार पांच साल की सबसे बड़ी रेटिंग रखता है, अपने पायलट एपिसोड को प्रसारित करता है।
1990 अमेरिका नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण करता है।
1992 फ्रांसीसी मतदाताओं ने मास्ट्रिच संधि को मंजूरी दी।
1995 संयुक्त राज्य महासभा का 50वां अधिवेशन हुआ।
2007 कनाडाई डॉलर 1976 के बाद पहली बार अमेरिकी डॉलर के साथ संक्षेप में पहुंच गया।
2007 अमेरिका के लुईसिआना में अपने श्वेत सहपाठी को प्रताड़ित करने के आरोप में सजा पाने वाले छह अश्वेत युवकों के समर्थन में 15000 से 20000 प्रदर्शनकारियों ने मार्च किया।

विपक्ष पर दबाव का अरविंद केजरीवाल का आतिशी दांव

ललित गर्ग

अरविंद केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने राजनीति में कुछ मौलिक प्रतिस्थापनाएं की है, बने-बनाये रास्तों पर न चलकर नये रास्ते इजाद किये हैं। वे संकटों को अवसर में बदलने वाले करिश्माई व्यक्तित्व भी हैं। उनकी राजनीति अनेक विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरी रही है, उनके व्यवहार एवं वचनों में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित होते रहे हैं, लेकिन ये ही विरोधाभास उनकी राजनीतिक चमक का कारण भी बने हैं। क्योंकि राजनीति में सब जायज माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने से खुद को बंधा महसूस करते हुए उन्होंने इस्तीफे का धारदार दांव चलाकर राजनीतिक जगत में एक हलचल पैदा कर दी। वहीं पार्टी में संभावनाओं भरे अनेक चेहरों के होने के बावजूद उन्होंने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वह वरिष्ठता क्रम में निचले पायदान पर खड़ी थी, लेकिन केजरीवाल ऐसे चौंकाने वाले फैसले पहले भी लेते रहे हैं। लेकिन इस तरह वे जनादेश का मज़ाक भी बनाते रहे हैं तो संवैधानिक स्थितियों की धता भी करते रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल साहस के कदम एवं चतुराई की आंख लेकर परम्परागत राजनीति की जंजीरों को तोड़कर आगे निकलते रहे हैं। संभावनाएं की जा रही थी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अधिक संभावनाएं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाये जाने की थी। क्योंकि क्षेत्रीय दलों में किसी राजनीतिक या कानूनी संकट के चलते परिवार के ही किसी सदस्य को सत्ता की बागडोर सौंप देने परंपरा रही है। ताकि स्थितियां सामान्य होने पर फिर मुख्यमंत्री की गद्दी आसानी से वापस ली जा सके। इसके अनेक उदाहरण है, जिनमें बिहार में चारा घोटाले में घिरने के बाद लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की बागडोर सौंपी थी। बहरहाल, केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपने तरकश से जो तीर चले हैं, उनकी धार एवं तीक्ष्णता को महसूस किया जा सकता है। इन तीरों से हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव समेत अन्य राष्ट्रीय मुद्दों में उलझी भाजपा व कांग्रेस पर केजरीवाल ने मनोवैज्ञानिक राजनीतिक दबाव तो बना ही दिया है। हरियाणा में स्वतंत्र चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर उन्होंने सत्ता के गठन में स्वयं को एक ताकतवर मोहरे के रूप में प्रस्तुत करने का चतुराई भरा खेल भी खेला है। दिल्ली में भी उन्होंने अपनी निस्तेज होती स्थितियों को मजबूती दी है।

दरअसल, केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन के योद्धा के रूप में वर्ष 2014 के इस्तीफे के दांव की तरह 2015 में आम आदमी पार्टी को मिली भारी जीत का अध्याय दोहरा देना चाहते हैं। लेकिन इस बार की स्थितियां खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होने से खासी चुनौतीपूर्ण व जोखिमभरी हैं। निस्संदेह, यह दांव मुश्किल भी पैदा कर सकता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। भले ही केजरीवाल अपने को, समय को पहचानने वाला साबित कर रहे हो, लेकिन वे अपने देश को, अपने पैरों की जमीन को एवं राजनीतिक मूल्यों को नहीं पहचान रहे हैं। 'आप' की राजनीति नियति भी विसंगति का खेल खेलती रहती है। पहले जेल जाने वालों को कुर्सी मिलती थी, अब कुर्सी वाले वाले जेल जा रहे हैं। यह नियति का व्यंग्य है या सबक? आप के शीर्ष नेताओं के लिये पहले श्रद्धा से सिर झुकता था अब शर्म से सिर झुकता है। कैसे आप की राजनीति इस शर्म के साथ जनता से मुखातिब होगी और जनता क्या जबाव देगी, यह भविष्य के गर्भ

में है। जिन अप्रत्याशित हालात में एवं बहुत कम समय के लिये आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, वे बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कई उदाहरण हाल के वर्षों में दिखे हैं, लेकिन यह मामला उन सबसे अलग है। पिछले करीब दो साल न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी इस मायने में चुनौतीपूर्ण रहे कि एक-एक कर उसके कई बड़े नेता और मंत्री जेल भेज दिए गए। दिल्ली का विकास मुफ्त की संस्कृति की भेट चढ़कर विकास को अवरुद्ध किये हुए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद संकट और गहराया। इन संकटपूर्ण हालातों में आतिशी ने पार्टी का प्रभावशाली ढंग से बचाव किया। उन्होंने सौरभ भारद्वाज और अन्य साथियों के साथ मिलकर सड़क से लेकर मीडिया तक आम आदमी पार्टी की जंग लड़ी, उससे कार्यकर्ताओं में उनकी एक जुझारू छवि बनी है। ऐसे में, उनसे उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। क्या अतिशी अपने राजनीतिक कौशल से यह पद पाया है या वे केजरीवाल की राजनीति का एक मोहरा-भर बनी है? उनके हिस्से में यह पद तब आया जब पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं-अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया-ने कह दिया कि वे नए सिरे से जनादेश हासिल करने के बाद ही पद पर बैठेंगे। अगर पार्टी जनादेश हासिल नहीं कर पाती तब तो उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा, अगर पार्टी चुनाव जीतती है तब भी मुख्यमंत्री पद से उनका हटना लगभग तय है। इन स्थितियों में कांटों भरा ताज पहनकर उनके कामकाज एवं प्रभावी नेतृत्व का क्या औचित्य है?

अतिशी एक वफादार एवं जिम्मेदार नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही है। पार्टी के लिये उनके समर्पण एवं अटूट निष्ठा की मुद्रा विधायक दल की नेता चुने जाने के वक्त भी सामने आयी, जब आतिशी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि वह सिर्फ अगले चुनाव तक पदभार संभाल रही हैं, पार्टी के भीतर किसी नए केंद्र की आशंका को तिरोहित करना तो है ही, कहीं न कहीं यह वरिष्ठ नेताओं की आहत महत्वाकांक्षाओं पर मरहम रखना भी है। आतिशी का यह पहला कार्यकाल है, और किसी गैर-राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिला का पांच साल के भीतर यूं मुख्यमंत्री की कुरसी तक पहुंचने का यह विरल उदाहरण भी है। अतिशी दिल्ली जैसे सुबे की मुखिया बनी हैं, जिस दिल्ली ने सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसी दिग्गज महिला नेताओं का शासन देखा है। कुल मिलाकर, दिल्ली में शुरू हुए आप के इस नए प्रयोग और उसके नतीजों पर सबकी नजरें होंगी।

अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव कराने की मांग की है, उनकी यह मांग अस्वीकृत हो गयी है, फिर भी अगले साल फरवरी के पहले पखवाड़े तक दिल्ली में चुनाव कराने होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सोची-समझी रणनीति के तहत ही दिया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी ईमानदारी के जनमत संग्रह के रूप में दर्शा सकें। उनका मकसद भाजपा सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला करने तथा खुद को राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार के रूप में दिखा जनता की सहानुभूति अर्जित करना भी है। लेकिन इस तरह की राजनीतिक चतुराई में अगर कोई आधार नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती तो दूसरों के लिए खोदे गए खड्डों में स्वयं एक दिन गिर जाने की स्थिति बन जाती है। कुछ लोग इस प्रकार से प्राप्त जीत की खुशी मनाते हैं, कुछ इस प्रकार की हार की खुशी मनाते हैं, जो कभी जीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गलत तरीकों से प्राप्त जीत से सिद्धांतों पर अडिग रहकर हारना सम्मानजनक होता है। निस्संदेह, जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र हासिल करने की योजना उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा जान पड़ती है।

केजरीवाल को अतिशी रूपी दांव से ज्यादा लाभ शराब घोटाले में नाम आने व गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते तो मिलता। ऐसे में, आतिशी के पास अपनी शासकीय छाप छोड़ने के साथ आप की राजनीतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में निश्चित रूप से उसकी लड़ाई भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी अपनी जमीन बचाने की होगी। दिल्ली के नागरिकों की अपेक्षाओ पर खरा उतरने के साथ-साथ पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने की चुनौती तो है ही। जाहिर है, आम आदमी पार्टी उनसे यही अपेक्षा करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का आलेख लिखे।

जम्मू-कश्मीर में छोटी पार्टियां निभा सकती हैं किंगमेकर की भूमिका

अनन्या मिश्रा

जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं। राज्य में जहां बड़ी पार्टियां जी-जान से जुटी हैं, तो वहीं सूबे की कुछ ऐसी छोटी पार्टियां भी हैं, जो किंगमेकर की भूमिका निभा सकती हैं और बड़ी पार्टियों का खेल भी बिगाड़ सकती हैं। इन छोटी पार्टियों में अपनी पार्टी, पीसी, डीपीएपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी शामिल है। पांच दशक पहले स्थापित पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को अब्दुल गनी लोन द्वारा स्थापित किया गया। वहीं अब इस पार्टी का नेतृत्व अब्दुल गनी लोन के बेटे और पूर्व मंत्री सज्जाद लोन कर रहे हैं। सूबे में उग्रवाद के दौरान पीसी ने चुनाव नहीं लड़ा और अपना चुनाव चिन्ह भी खो दिया था। लेकिन साल 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान सज्जाद लोन हंदवाड़ा से निर्वाचित हुए। फिर पार्टी ने कुपवाड़ा से भी जीत हासिल की और पीडीपी-बीजेपी से हाथ मिला लिया। वह सरकार गिरने तक लोन कैबिनेट मंत्री बने रहे। इस बार वह वह 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फौरन बाद अपनी पार्टी का गठन किया। वह पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले सूबे के पहले राजनेता थे। अपनी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होने जा रही है। यह पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दौरान अपनी पार्टी को झटका लगा था। अपनी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने श्रीनगर और अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीटों पर अपनी जमानत खो दी थी। साल 2022 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की स्थापना की थी। यह सूबे के राजनीतिक परिदृश्य में नई पार्टी है। आजाद ने कांग्रेस से करीब 5 दशक लंबे जुड़ाव को खत्म कर डीपीएपी की स्थापना की थी। आजाद अपनी पार्टी को एनसी और पीडीपी जैसी क्षेत्रीय ताकतों के लिए एक ऑप्शन के तौर पर पेश करना चाहते थे। हालांकि वह पहले राजनीतिक परीक्षण में विफल हो गए और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी के सभी तीन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। बता दें कि साल 2012 में बारमूला सांसद इंजीनियर राशिद ने अवामी इत्तेहाद पार्टी की स्थापना की थी। साल 2009 और 2014 में लैंगेट से निर्दलीय के रूप में उत्तरी कश्मीर के फायरब्रांड नेता जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए। साल 2019 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था और करीब 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसके बाद आश्चर्य यह रहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तिहाड़ जेल में रहते हुए राशिद ने बारामूला में एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीसी अध्यक्ष सज्जाद लोन को बड़े अंतर से हराया था। फिर जेल से अंतरिम जमानत पर रिहाई के बाद अब वह पूरे कश्मीर में प्रचार कर रहे हैं, उनका युवाओं में खासा प्रभाव देखने को मिलता है।

बुलडोजर न्याय कितना उचित?

रोहित कौशिक

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में अभियुक्त की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख 1 अक्तूबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना कोई तोडफ़ोड़ नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों व जलाशयों के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने अवैध तरीके से की कई ऐसी कार्रवाई को संविधान के मूल्यों के विरुद्ध माना है। पिछले दिनों बुलडोजर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हुई बहस में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बुलडोजर वही व्यक्ति चला सकता है, जिसमें बुलडोजर चलाने की क्षमता हो।

बुलडोजर चलाने के लिए दिल, दिमाग और हिम्मत की जरूरत होती है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार में निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। किसान परेशान हैं और नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश का बुलडोजर गोरखपुर की ओर मुड़ जाएगा। कुछ समय पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि क्या किसी का मकान सिर्फ इसलिए गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण या सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। कुछ वर्षों से बुलडोजर को अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरैंस पॉलिसी के तहत प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किए जाने का प्रचलन बढ़ रहा था।

सरकारों के इस व्यवहार पर कई तरह के सवाल उठ

र हे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाना शुरू किया था। इस कदम से एक विचारधारा के लोगों में योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय हुए और उन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई को देखकर ही अन्य राज्यों विशेषत: मध्यप्रदेश में भी बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ी थी। मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलते हुए अप्रैल 2022 में खरगौन में साम्प्रदायिक झड़पों के बाद बुलडोजर के इस्तेमाल का समर्थन किया था। उनकी सरकार ने 16 घर और 29 ढांचे ध्वस्त कर दिए थे। शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा जाने लगा था। हरियाणा में भी बुलडोजर के माध्यम से तथाकथित न्याय देने की कोशिश की गई थी। हरियाणा के नूंह में विश्व हिन्दू परिषद की यात्रा के दौरान भड़के साम्प्रदायिक दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया था।

दिल्ली में 16 अप्रैल 2022 को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान साम्प्रदायिक ड्क्षहसा भड़कने के बाद तत्कालीन भाजपा के नेतृत्व वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक मस्जिद के सामने के गेट और दीवार समेत कई संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया था। हाल ही में 22 अगस्त को मध्यप्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के घर को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया था और उनकी गाडिय़ों को भी तहस-नहस कर दिया गया था। उन पर छतरपुर शहर कोतवाली घेरकर प्रदर्शन करने और पुलिस पर पत्थरबाजी का आरोप लगा था। इस संबध में जमीयत-उलेमा-ए हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर न्याय का विरोध करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त भी सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय के खिलाफ अनेक याचिकाएं दायर की गई थीं।

काफी लोग अपराधियों के खात्मे के लिए बुलडोजर न्याय को सही ठहराते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बुलडोजर से ही न्याय देना है तो देश में न्यायालय का क्या काम है? संविधान विशेषज्ञों का भी मानना है कि बुलडोजर न्याय संविधान सम्मत नहीं है। आरोपियों को फटाफट दोषी घोषित कर देना और न्यायालय को नकारकर स्वयं ही बुलडोजर चलवाना भला संविधान सम्मत कैसे हो सकता है? कटु सत्य तो यह है कि अधिकांश मामलों में बुलडोजर एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ चलाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है।

सवाल यह है कि जब व्यक्ति को किसी अपराध का आरोपी घोषित किया जाता है, तभी उसके अवैध निर्माण का पता क्यों चलता है। सवाल यह भी है कि सत्ता पक्ष के कितने लोगों पर बुलडोजर चलाया गया है? जब एक राजनीति के तहत बुलडोजर चलाया जाएगा तो उस पर सवाल उठेंगे ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में भू-माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर न्याय इसलिए भी असंवैधानिक है क्योंकि जब घर को ध्वस्त किया जाता है तो उससे परिवार के वे लोग भी प्रभावित होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती है।

भारतीय मुसलमानों को पीड़ित बताने वाले ईरान को आईना

अभिनय आकाश

ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। मोहम्मद साहब उसके सच्चे रसूल हैं। इस्लाम को मानने वाले दुनियाभर के मुसलमान खुद को इस्लाम के अनुयायी कहते हैं। लेकिन इस्लामी कानून की अपनी समझ और इसके इतिहास के मुताबिक इस्लाम के मानने वाले मुसलमान कई पंथों में बंटे हुए हैं। शिया और सुन्नी मुस्लिमों ने अलग-अलग विचारधारा अपना ली। सुन्नी मुस्लिमों ने सेक्युलर लीडरशिप चुनी। वहीं दूसरी ओर शिया मुस्लिम इमामों को अपना धार्मिक नेता मानते हैं, जिन्हें वह पैगंबर मोहम्मद के परिवार द्वारा नियुक्त किया हुआ मानते हैं। लेकिन शिया और सुन्नी के विवाद की अक्सर कहानी देखने और पढ़ने को मिलती रहती हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनई ने कहा है कि भारत में मुसलमानो का उत्पीड़न हो रहा है। हालांकि भारत ने ईरान को आईना दिखा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले ईरान का अपना खुद का रिकॉर्ड इस मामले में बेहद खराब है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसे इसको लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। ईरान इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के निशाने पर भी रहता है। ईरान के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार देश की कुल आबादी में 99.4 प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती है। जिसमें 90 से 95 प्रतिशत शिया और पांच प्रतिशत के लगभग सुन्नी मुसलमान हैं।

पैगबंर मोहम्मद की जयंती पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को गाजा और म्यांमार में पीड़ित मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। खामनेई ने अपने पोस्ट में लिखा था कि इस्लाम के दुश्मन हमेशा हमें इस्लामी उम्माह के तहत हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी

और देश में मुसलमान की पीड़ा से अंजान हैं तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते।

ये बयान भारत को गाजा में घट रहे त्रासदी के साथ तो जोड़ता ही है। साथ ही इसे दुनियाभर में मुसलमानों के साथ हो रही हिंसा से भी जोड़ता है। खामनेई के इस ट्वीट के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी कड़ी निंदा की। एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने जो भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में टिप्पणी की है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित है और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखे।

एक तरफ खामनेई भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं और उसी वक्त महिलाओं पर अत्याचार और अभिव्यक्ति की आजादी को सिमित करने के लिए ईरान की आलोचना की जा रही है। दिलचस्प ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का ट्वीट 16 सितंबर को आया है। ठीक दो साल पहले 16 सितंबर 2022 को ही महसा अमिनि नाम की ईरानी युवती की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। वो सिर्फ 22 साल की थी। उसे इस्लामिक ड्रेस कोड का पालन न करने के चलते गिरफ्तार किया गया था। कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। मौत से देशभर में व्यापक प्रदर्शन का दौर देखने को मिला था। 16 सितंबर 2024 को 34 ईरानी महिला कैदी भूख हड़ताल पर चली गई हैं और दर्जनों लोग उनकी मृत्यु को याद करने के लिए हिजाब वाले नियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

भारत को अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देने वाले ईरान का इस मामले में रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि बहाई, ईसाई, गोनाबाड़ी दरवेश, यहूदी, सुन्नी मुस्लिम और यारेसन सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को कानून में भेदभाव का सामना करना पड़ा हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, बच्चे को गोद लेने, राजनीतिक कार्यालयों और धार्मिक स्थलों तक पहुंच शामिल है। सैकड़ों लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है। उनके खिलाफ अन्नयायपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया और यातनाएं दी गई।

बहाई अल्पसंख्यक लोगों के साथ ईरान में भेदभाव होता है। इनके हाई एजुकेशन पर बैन है और बिजनेस को जबरन बंद करना या उनकी संपत्तियों को जब्त करना, साथ ही बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से हिरासत में लेना तो आम बात है। अधिकारियों ने तेहरान में दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे कब्रिस्तान में बहाई लोगों को दफनाने से भी रोक दिया और कई मृतक बहाई लोगों को जबरन पास के खवारन सामूहिक कब्र स्थल पर दफना दिया, जिसके बारे में माना जाता है कि वहां 1988 में जेल में हुए नरसंहार के पीड़ितों के अवशेष हैं। इस समुदाय को संविधान में दर्जा तक नहीं मिला है और संसद में इसके लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है।

ईरान में लगभग 5 मिलियन अफ़गान नागरिकों को व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, आवास, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सेवाएँ और कहीं भी आने जाने की आजादी से जुड़ी पाबंदियां शामिल हैं। सरकारी मीडिया और कुछ अधिकारियों ने अफ़गान शरणार्थियों के खिलाफ़ तीखी आलोचना की, जिससे ईरान में अफ़गान नागरिकों के खिलाफ़ नफ़रत भरे भाषण और घृणा अपराधों को बढ़ावा मिला।

घाटी की सियासत में नई पटकथा लिखेगा विस चुनाव

शाहरुख खान

इस बार का जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव घाटी की सियासत में नई पटकथा लिख रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विस चुनाव हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार राज्य के लोग मतदान करेंगे। जमात-ए-इस्लामी के नेता साल 1987 के बाद से चुनावों का लगातार बहिष्कार करते आए हैं, लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जमात के कई नेताओं ने वोट डालकर लोगों को हैरान किया। अब विस चुनाव भी घाटी की छवि व विचारधारा बदलने का चुनाव होगा। दरअसल, जम्मू-कश्मीर का नाम आते ही देश के आम आदमी के दिमाग में जो छवि उभरती है, वह सिर्फ खूबसूरत वादियों की नहीं होती है। पत्थरबाजी, अलगाववाद, मुठभेड़ समेत अन्य चीजें भी उभरती हैं। राज्य के लोग भी इनसे थक चुके हैं और वह विकास के रास्ते पर चलने को तैयार हैं। इसका संदेश वह लोकसभा चुनाव में बंपर मतदान से दे चुके हैं। ऐसे में यह

चुनाव राजनीतिक-सामाजिक समीकरण भी बदल रहा है। करीब 37 साल चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ रहे जमात-ए-इस्लामी के नेता इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि वह इस चुनाव के जरिए कश्मीर के मुद्दों का हल चाहते हैं। इस संगठन की मौजूदगी कश्मीर के सोपोर, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा में मजबूत है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु सोपोर क्षेत्र से मैदान में हैं। इसी तरह जेल से चुनाव लड़ रहे सरजन अहमद वागे घाटी में होने वाली विरोध रैलियों का प्रमुख चेहरा रहते थे। अब वह भी पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव का पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2014 के विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो उसमें अलगाववादी समूहों ने बहिष्कार किया था और लोगों से भी अपील की थी कि वोट न करें उसके बावजूद करीब 66 फीसदी मतदान हुआ था। 13 निर्वाचन क्षेत्रों में यह 70 प्रतिशत से अधिक था और 50 फीसदी तो कई सीट पर रहा। पहली लड़ाई ही मतदान प्रतिशत को पुराने आंकड़े के पार लेकर जाना होगा। यहीं से बदलाव के संकेत दिखाई देंगे। इस राज्य के लिए यही शुभ संकेत हैं कि जो लोकतंत्र के विरोधी थे वे सभी इसका हिस्सा बन रहे हैं और भविष्य में यहां की अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। अनुच्छेद-370 हटने के बाद अस्तित्व में आए केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 2014 में जब अंतिम बार विधानसभा चुनाव हुआ था तो जम्मू-कश्मीर राज्य था और लद्दाख भी इसका भाग था। तब पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार बनी थी, जो जून 2018 में भंग हो गई। इसके बाद से जम्मू-कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। अब इस चुनाव के बाद राज्य को नई सरकार मिलेगी। कानपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉ. सुमन शुक्ला ने कहा घाटी में अलगाववादी हमेशा ही लोकतंत्र का विरोध करते रहे हैं। वह भी चुनावी प्रक्रिया के रास्ते से समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। यह बदलाव न कि सिर्फ लोकतंत्र बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए शुभ संकेत हैं। मौलवी सरजन अहमद वागे घाटी में होने वाली विरोध रैलियों का प्रमुख चेहरा माने जाते रहे हैं, अब वह भी चुनावी मैदान में हैं। यह बदलाव अच्छा है और यह चुनाव इस राज्य की दिशा तय करेगा। चुनाव विश्लेषक दीपक गुप्ता ने कहा निकाय चुनाव होने के बाद से ही माहौल बदल गया था। वहीं से स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआत हो गई। यह चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। हां एक समस्या भविष्य में देखने को मिल सकती है कि यह अब केंद्र शासित राज्य है और यहां के मुख्यमंत्री को उतने अधिकार नहीं मिलेंगे तो यह बड़े-बड़े वादे कैसे पूरे करेंगे। केंद्र सरकार या तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे या फिर मुख्यमंत्री की शक्तियां बढ़ाए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी सुबह है।

इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य है कि खाद्यान्न में यह वृद्धि से अधिक रही है जो कि संतोषजनक स्थिति है और अभी तो भोजन पेट भर मिल रहा है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या 2025 में हमें पेट भर भोजन प्राप्त होगा? अगर नहीं तो हम आगे क्या करेंगे?

टिकाऊ खेती आज की आवश्यकता

जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पादन

भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.7 करोड़ को छू चुकी है जो 1991-2000 तक 1.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि में रही, जबकि खाद्यान्न उत्पादन 2003-04 में 213.5 मिलियन टन तक पहुंचा अर्थात् 2.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से.

इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य है कि खाद्यान्न में यह वृद्धि से अधिक रही है जो कि संतोषजनक स्थिति है और अभी तो भोजन पेट भर मिल रहा है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या 2025 में हमें पेट भर भोजन प्राप्त होगा? अगर नहीं तो हम आगे क्या करेंगे?

हमें आगे भी 21वीं सदी के बाद से खाद्यान्न में लगभग 25-30 प्रतिशत की वृद्धि कायम रखनी होगी अन्यथा पूरा देश हमारा सूखा घोषित हो जायेगा जिससे की लगभग 14 प्रतिशत उत्पादन में गिरावट होगी जो भविष्य के लिए प्रगति के उत्तम संकेत नहीं हैं.

भूमि-जल पर्यावरण

खेती में उर्वरकों, कीटनाशकों शाकनाशियों अर्थात् रसायनों के अत्यधिक प्रयोग में भूमि की दशा निश्चय ही खराब हुई है. जिससे की भूमि के लाभदायक कीट, केंचुए, जीवाणु इत्यादि नष्ट हुए हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म तत्वों में भी भारी कमी हुई. अतः जीवांश खादों के प्रयोग से हम रोक सकते हैं फसल चक्र अपना सकते हैं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कर सकते हैं कई जंगल भी नष्ट किये गये सघन पद्धतियों के प्रयोग के कारण जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है अर्थात् इसका दोहन कम किया जाए एवं इन्हें संरक्षित किया जाने का प्रयास करना नितांत आवश्यक है.

लाभ/खर्च अनुपात

हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की उपलब्धि बनाये रखने के लिए सस्य रसायनों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है. जिससे की हमारी भूमि में मृदा में तथा मृदा के गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है. यदि यह प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलती रही तो भूमि एवं जल की उपादेयता समाप्त हो जायेगी और नई पीढ़ी का जीवन ही असुरक्षित हो जायेगा वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र बराबर कम होता जा रहा है. ऐसी परिस्थिति में हम टिकाऊ खेती का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है तथा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि वर्तमान व भविष्य दोनों में संतुलन हो. इस प्रकार की खेती का प्रयोग करके हम अपने भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित तो कर रही है बल्कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं सुरक्षा करके या उन्हें सुरक्षित बनाये रखने का कर्त्तव्य भी पूरी तरह निभा रहे हैं. अर्थात् हमें टिकाऊ खेती का प्रयोग किया जाना चाहिए. जिसके द्वारा हमें आर्थिक लाभ एवं भारत सरकार को पूर्णतः उत्पादन से लाभ प्राप्त हो सके.

कृषि क्षेत्र में सम्पन्नता लाने के लिए उत्पादकता टिकाऊपन तथा समानता की बहुत जरूरत है हमें भारत में भी बदलते पर्यावरण में कृषि निर्वाह की प्राथमिकता देनी अनिवार्य आवश्यकता है. इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में हम आर्थिक दृष्टि से कारगर, पर्यावरण की दृष्टि त्रुटीहीन सामयिक दृष्टि से सुसंगत प्रौद्योगिकी जो कम लागत पर अधिक से अधिक कृषि उत्पाद दे सकें.

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टिकाऊ खेती मानव जाति को निरंतर खुशहाली प्रदान का वचन देती है.

टिकाऊ खेती का महत्व

टिकाऊ खेती का महत्व सबसे अधिक वर्तमान खेती की प्रणालियों, तरीकों एवं समस्याओं को सुधारने में है. टिकाऊ खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं मृदा, जल, ऊर्जा, वन-विकास एवं जंगली पशुओं की सुरक्षा या इन्हें सुरक्षित रखने से है. टिकाऊ खेती में इनके प्रबंधन पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता है. कई प्रकार की उत्पन्न समस्याओं जैसे- सौर ऊर्जा का उचित प्रयोग, वातावरण प्रदूषण की रोकथाम पर्यावरण का संतुलन डगमगाना इत्यादि समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना ही इसमें निम्न विषय है अर्थात् भविष्य में टिकाऊ खेती के माध्यम से इन समस्याओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है.

टिकाऊ खेती का लाभः

- पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाये रखने में टिकाऊ खेती का प्रमुख कार्य है.
- वातावरणीय प्रदूषण कम होता है.
- लगाई फसलों की उत्पादन लागत कम आती है.
- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उचित प्रकार से करते हैं.
- टिकाऊ खेती में भूमि, जल, ऊर्जा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इसका प्रयोग एवं दोहन ध्यान रखकर कर सकें.

धनिया की उन्नत खेती

धनिया हमारे दैनिक उपयोग के मसालों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो पूरे वर्ष सम्पूर्ण देश में उगाया जाता है इसलिए पूरे वर्ष आय का साधन हो सकता है, हरी पतियां सब्जियों में उपयोग की जाती हैं। धनिया में मधुर सुगंध कोरोमिन्डाल, लिनाकोल, एल्कोहल पदार्थ उपस्थिति के कारण होता है। सूखे धनिया के बीजों को रबी में बोया जाता है। मध्यप्रदेश का 70 प्रतिशत धनिया गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, दतिया जिले में उगाया जाता है इसके अलावा शाजापुर, मंदसौर, राजगढ़ जिलों में भी बोया जाता है। अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण उपज के लिये उन्नत तकनीक अपनाना आवश्यक है।

भूमि

असिंचित धनिया के लिये काली मिट्टी जिसकी जलधारण क्षमता एवं जल निकास वाली अच्छी भूमि हो और सिंचित धनिया बोने के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है जिसमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त हो।

खेत की तैयारी

असिंचित क्षेत्र में अंतिम वर्षा जल की नमी को संरक्षित करते हुए 2-3 जुताई कर यथाशीघ्र बुवाई करें तथा सिंचित खेत में खरीफ फसल की कटाई के बाद 2-3 जुताई करें।

बुवाई का समय

रबी में बुवाई के लिये 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक उपयुक्त समय है। देरी बुवाई करने पर भभूतिया रोग की संभावना बढ़ जाती है।

उन्नत जातियां

साधना,पंत हरितिमा, गुजरात धनिया, सिंधु,स्वाति, उदयपुर धनियां-20

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन

खेत की तैयारी के समय 15-20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद खेत में मिला दें। सिंचित अवस्था में प्रति हेक्टर 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 किलोग्राम पोटाश पर्याप्त होता है। जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा आधार खाद के रूप में बुवाई के समय बीज के नीचे ऊर कर दें तथा शेष नत्रजन की मात्रा प्रथम एवं द्वितीय सिंचाई के समय दें उस समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है।

बीज की मात्रा एवं बुवाई विधि

सिंचित अवस्था में बीज दर 12-15 किलो ग्राम तथा असिंचित अवस्था में 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। जिसे बुवाई पूर्व बीज को 24 घंटे पानी में भिगो कर रखें जिससे अंकुरण शीघ्र और अच्छा होता है। इसके बाद थाइरम या डाइथेम -एम 45 की 3 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज उपचारित कर बोयें। बुवाई कतारों में की जाती है जिसमें कतार से कतार की दूरी 25-30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 5-7 सेमी रखें और बीज को 3-5 सेमी गहराई पर बुवाई करें।

निंदाई एवं गुड़ाई

धनिये की फसल में प्रथम निराई गुड़ाई बुवाई के 25-30 दिन पर करना चाहिये जिसमें जहां अधिक पौधे उगे हों वहां से पौधे उखाड़ दें।

सिंचाई

अच्छी पैदावार के लिये फसल की क्रान्तिक अवस्थायें - जैसे शाखायें फूटते समय, फूल आते समय, बीज बनते समय खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। सिंचाई 10-15 दिन के अंतराल पर करें जो मिट्टी की किस्म और मौसम पर निर्भर करता है।

फसल उत्पादन

धनिया की फसल बीज के लिये 140-150 दिन में तैयार हो जाती है। बीज के रूप में 15 से 20 क्विं. प्रति हेक्टर उत्पादन प्राप्त होता है। पतियों के रूप में बोने के 45 दिन पश्चात से पतियों की कटाई कर विक्रय किया जा सकता है।

धनिया कटाई के बाद प्रबंधन

- फसल अवधि पूर्ण होने के पश्चात जब दाने परिपक्व हो जाये एवं दाने हरे रहें तब उसे काटकर छायादार स्थान में सुखाना चाहिए। दाने हरे रंग के रहने से बाजार में अधिक कीमत मिलती

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणापत्र

चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव का घोषणापत्र जारी कर दिया। घोषणापत्र पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। घोषणापत्र के अनुसार, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये दिए जाएंगे। आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस दौरान नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लोगों की नजरों में एक पतला दस्तावेज बना दिया। कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने घोषणा पत्र की प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया। उनके लिए ये दस्तावेज... महज एक औपचारिकता है व लोगों के साथ छलावा करना है।

मुख्यमंत्री के तौर पर 21 को शपथ लेंगी आतिशी

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी शनिवार (21 सितंबर 2024) को कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सत्तारूढ़ दल ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के मंत्रालय में वित्त, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, बिजली, महिला और बाल विकास आदि को संभाला था। केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं था। नए मंत्रिमंडल में ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। दिल्ली की नामित मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे जबकि चार मंत्री बरकरार रहेंगे। %आप% ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री नामित की गई आतिशी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी 21 सितंबर को पद की शपथ लेंगे।

नवादा कांड को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में कथित आगजनी की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें दलित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। जमीन विवाद को लेकर बुधवार शाम कथित तौर पर करीब 80 घरों में आग लगा दी गई। नीतीश कुमार ने बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नवादा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा एक तथ्यान्वेषी दल भी मौके पर भेजा गया था। सत्तारूढ़ जद (यू) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि दलितों को डरना नहीं चाहिए, जबकि विपक्ष ने बिहार सरकार पर उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होने का आरोप लगाया। एक वीडियो संदेश में, रंजन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन दिया।

बिहार में कोई कानून-व्यवस्था नहीं : लालू यादव

पटना। बिहार के नवादा में कथित तौर पर भूमि विवाद को लेकर कई घरों में आग लगाए जाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इन सबे के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। लालू ने कहा कि यह बहुत गलत है। बिहार में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार (बिहार के सीएम) विफल हो गए हैं। वहीं, तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, बिहार में आपकी डबल इंजन पॉवर्ड सरकार में दलितों के घर जला दिए गए है। उन्होंने कहा कि यह भारत देश की ही घटना है। कृपया इस मंगलराज पर दो शब्द तो कह दिजीए कि यह सब प्रभु की मर्जी से हो रहा है इसपर एनडीए के बड़बोले शक्तिशाली नेताओं का कोई वश नहीं है।

महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में देरी से कांग्रेस पर भड़के राउत

मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों पक्षों ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है। हालाँकि एमवीए में तनाव बढ़ता जा रहा है। बातचीत शुरू तो हो गई थी लेकिन वह बढ़ नहीं सकी है। यही कारण है कि शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इसको लेकर निराशा जताया है। संजय राउत ने विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत में देरी के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन दिनों बहुत व्यस्त है, लेकिन फिर भी हमने इसे (बातचीत) खत्म करने के लिए उन्हें बुलाया है। हमने कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया है। वे इतने व्यस्त हैं कि हर दिन तारीख पे तारीख होती है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अगले तीन दिनों तक एक साथ बैठेंगे।

श्रीनगर की रैली में बोले मोदी- आज जम्मू-कश्मीर में बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं, पेन-किताबें हैं

अब तीन खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेंगे लोग

श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में है। उन्होंने वहां सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए तीन चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हुआ था, अन्य दो चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। नौजवानों का ये उत्साह, बुजुर्गों की आंखों में शांति का संदेश और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं-बहनें... ये नया कश्मीर है।

मोदी ने कहा कि हम सबका मकसद जम्मू-कश्मीर की तेज तरक्की है। जम्मू-कश्मीर की तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने के पैगाम के साथ आज मैं आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं कि आज मेरे कश्मीर के भाई-बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में इस वक्त जम्हूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि किश्तवाड़ में 80% से ज्यादा वोटिंग, डोडा में 71% से ज्यादा वोटिंग, रामबन में 70% से ज्यादा और कुलगाम में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास बना है, ये नया इतिहास जम्मू-कश्मीर के लोगों ने रचा है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि जम्मू-कश्मीर के लोग किस तरह भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूं!

विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू-कश्मीर आया था... तो मैंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर की बर्बादी के लिए तीन खानदान जिम्मेदार हैं। तब से, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है कि

इनपर कोई कैसे सवाल उठा सकता है, इन्हें लगता है कि जैसे-तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना इनका पैदाइशी हक है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की अवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही, इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने, जम्मू-कश्मीर को सिर्फ, तशद्दुत यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू-कश्मीर, इन तीन खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू-कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना...जम्मू-कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना...यहां के नौजवानों को, यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना... ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। उन्होंने कहा कि हमारी एक और पीढ़ी को मैं इन 3 खानदानों के हाथों तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए, यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू-कश्मीर में स्कूल-कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती, बल्कि आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी बनने की खबरें आ रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, मासूम बच्चों ने क्या गुनाह किया था कि उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा? यह दुर्भाग्यपूर्ण था। आज, हमने 50,000 बच्चों की स्कूल वापसी सुनिश्चित की है। हमने 15,000 स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की हैं, जिससे 1.5 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 250 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों में अपग्रेड किया जा रहा है। आज तीन खानदानों (पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस) के पास बोलने के लिए कुछ नहीं।

कांग्रेस हो या पाकिस्तान, दोनों के इरादे और एजेंडा एक : शाह

- **पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथ लिया**

नई दिल्ली। भाजपा ने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस गठबंधन पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय तक सभी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथ लिया।

अमित शाह ने कहा, %पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35ए पर कांग्रेस-एनसी के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं।%

उन्होंने आगे कहा, %एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हों, या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देशविरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए, कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद।

वहीं, भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, %पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है। वह कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का समर्थन करता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए को बहाल करने के लिए एक ही ओर हैं। ऐसा कैसे है कि पत्रू से लेकर पाकिस्तान तक, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के विरोधी लोगों के पक्ष में दिखाई देती है?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था?

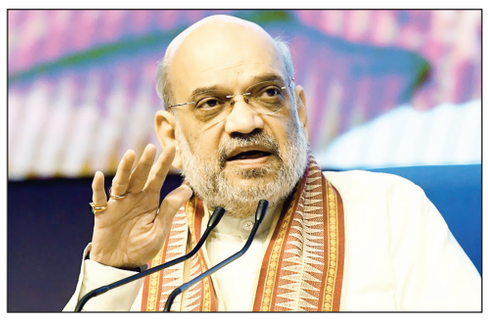

पाकिस्तान के एक टीवी कार्यक्रम में वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शामिल हुए। इस दौरान एंकर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया और

कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35ए जब लागू किया गया था तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस के पंडित नेहरू और जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला सत्ता में थे। अब एक बार फिर दोनों साथ आए हैं और दोनों ने कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35ए लागू करने का वादा किया है। इसे लेकर ख्वाजा आसिफ की प्रतिक्रिया मांगी गई। जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा और हम आर्टिकल 370 और 35ए पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों के रुख के साथ हैं।

8 अक्टूबर तक प्रतीक्षा करें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा : फारुक अब्दुल्ला

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को लेकर कांग्रेस व नेशन कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद जेकेएनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। फारुक अब्दुल्ला ने कहा मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्या कहता है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं एक भारतीय नागरिक हूं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों पर 8 अक्टूबर तक प्रतीक्षा करें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

पाकिस्तान को हमसे क्या लेना-देना, पहले अपना मुल्क संभालें : उमर अब्दुल्ला

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को लेकर भाजपा, कांग्रेस-एनसी गठबंधन पर हमलावर हो गई है। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने भीतर देखने की जरूरत है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान का हमसे क्या लेना-देना? हम पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं हैं, उन्हें अपने देश का ख्याल रखने दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमारे चुनावों में हस्तक्षेप करना चाहिए या हमारे चुनावों पर टिप्पणी करनी चाहिए। उन्हें अपना लोकतंत्र बचाना चाहिए, हम अपने लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि पीएम मोदी ने आज श्रीनगर में क्या कहा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने तीन परिवारों पर बात की होगी, लेकिन यह नहीं कि पिछले 5-6 साल जम्मू-कश्मीर में कैसे बर्बाद हुए हैं।

उन्होंने कहा कि आखिरी बार पीएम मोदी ने संसद में किसी सवाल का जवाब कब दिया था? हम जीतने के बाद हर सवाल का जवाब देने वाले लोग हैं, हम कहीं छिपते नहीं हैं।

बीजेपी ने पूछा- ये रिश्ता क्या कहलाता है?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन एक पेज पर है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर बयान आने के बाद देश में सियासत तेज होना तो निश्चित ही था। पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई। फिर बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और एनसी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस पार्टी और एनसी के इस रिश्ते को क्या कहा जाए? बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हम देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस लगातार पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले फारुक अब्दुल्ला ने कहा मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्या कहता है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं एक भारतीय नागरिक हूं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों पर 8 अक्टूबर तक प्रतीक्षा करें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

खेल
प्रमुख समाचार

अश्विन ने चेपॉक में लगातार दूसरा शतक जड़ा

चेन्नई। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर

रविचंद्रन अश्विन ने जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जारी टेस्ट मुकाबले में वह संकटमोचक साबित हुए हैं। उन्होंने चेपॉक में शतकीय पारी खेलकर भारत का स्कोर 300 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। दिलचस्प बात यह है कि चेपॉक में यह अश्विन के बल्ले से निकला लगातार दूसरा शतक है।

भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर का 101वां मुकाबला खेल रहे हैं। इसमें उन्होंने शानदार शतक जड़ा है। 38 वर्षीय बल्लेबाज ने 108 गेंदों में करियर का छठा शतक जड़ा। इससे पहले चेपॉक में ही उन्होंने करियर का पांचवां टेस्ट शतक जड़ा था। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अश्विन ने 106 रनों की दमदार पारी खेली थी।

भारत और बांग्लादेश के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी। 34 के स्कोर पर तीन विकेट गिर चुके थे। इसके बाद मोर्चा ऋषभ पंत ने संभाला। उन्होंने जायसवाल के साथ 62 रनों की साझेदारी निभाई। हालांकि, 26वें ओवर में हसन महमूद ने उन्हें आउट कर दिया। वहीं, जायसवाल 56 और केएल राहुल 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मोर्चा रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने संभाला। गुरुवार को आठवें नंबर पर उतरे अश्विन ने जडेजा के साथ मोर्चा संभाला और 186* रनों की साझेदारी निभाई।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स-निफ्टी रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई पर

नईदिल्ली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा चार साल से ज्यादा समय में ब्याज दर में पहली कटौती की घोषणा के बाद मजबूत वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाते हुए भारतीय शेयर बाजार में आज फिर से तेजी लौट आई। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स, ब्रस्य सेंसेक्स और निफ्टी ने गुरुवार को रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई पर कारोबार को समाप्त किया। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 236.57 अंक या 0.29 प्रतिशत की बढ़त लेकर 83,184.80 के उच्च स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे कारोबार के दौरान यह इंडेक्स 83,773.61 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 38.25 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 25,415.80 के नए शिखर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की ही तरह, इंट्राडे कारोबार के दौरान यह इंडेक्स 25,611.95 के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयर हरे निशान पर बंद हुए।

अगले 10 वर्षों में भारत में जिंक की खपत 20 लाख टन से अधिक होने की उम्मीद

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय जस्ता संघ (आईजेडए) ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की जस्ता की खपत अगले 10 वर्षों में वर्तमान 11 लाख टन से बढ़कर 20 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। 'जिंक कॉलेज' 2024 कार्यक्रम से इतर आईजेडए के कार्यकारी निदेशक एंड्रयू ग्रीन ने कहा, '' भारत में जस्ता की खपत व मांग 11 लाख टन है, जो भारत में वर्तमान उत्पादन से अधिक है। अगले 10 वर्षों में इसके 20 लाख टन से अधिक पहुंचने की संभावना है। यह एक अनुमान है।'' 'जिंक कॉलेज' का आयोजन हर दो साल में अंतरराष्ट्रीय जस्ता संघ (आईजेडए) द्वारा सदस्य कंपनी के साथ साझेदारी में किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, 'जिंक कॉलेज' 2024 की साझेदार है।

अमेरिकी ब्याज दर में कटौती से भारत में विदेशी निवेश पर असर पड़ने की संभावना नहीं: डीईए

नईदिल्ली। आर्थिक मामलों के सचिव (डीईए) अजय सेठ ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज दर में कटौती का भारत में विदेशी निवेश पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने वह किया है जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए सही लगता है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों में कटौती का फैसला करेगा। सेठ ने यहां पत्रकारों से कहा, '' यह भारतीय अर्थव्यवस्था सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। यह उच्च स्तर से 50 आधार अंकों की कटौती है। मुझे नहीं लगता कि इससे निवेश पर कोई खास असर पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि (अमेरिकी ब्याज दरों का) स्तर कहां हैं।

सीईएससी की शाखा ने 686.85 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए किया समझौता

नईदिल्ली। सीईएससी की शाखा पूर्वा ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड ने 686.85 मेगावाट तक की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए इकोरेन एनर्जी इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीईएससी लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, इकोरेन एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न तो संबंधित पक्ष है और न ही इसके प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का हिस्सा है। कंपनी सूचना के अनुसार, '' उसकी अनुषंगी कंपनी पूर्वा ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड ने 686.85 मेगावाट तक की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए इकोरेन एनर्जी इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।'' कंपनी ने कहा कि परियोजना तीन वर्षों के भीतर पूरी हो जाएगी।

भारत के मार्च 2026 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संकेत

प्रह्लाद सबनानी

भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.93 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। जबकि, जापान के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.21 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है एवं जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.59 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष बनी हुई है और जापान एवं जर्मनी की आर्थिक विकास दर लगभग स्थिर है अथवा इसके ऋणात्मक रहने की भी प्रबल सम्भावना है। इस दृष्टि से मार्च 2025 तक भारत जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एवं मार्च 2026 तक भारत जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही के समय में जर्मनी एवं जापान की अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर हैं, जिनके कारण इन दोनों देशों की आर्थिक विकास दर आगे आने वाले वर्षों में विपरीत रूप से प्रभावित रह सकती है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगातार 4 दशकों तक जर्मनी पूरे यूरोपीयन यूनियन में तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा। इस दौरान विनिर्माण इकाईयों के बल पर जर्मनी ने अपने आप को विश्व में विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया था एवं विभिन्न उत्पादों, विशेष रूप से कार, मशीनरी एवं केमिकल उत्पादों का निर्यात पूरे विश्व को भारी मात्रा में किया जाने लगा था। पिछले 20 वर्षों के दौरान जर्मनी पूरे यूरोपीयन यूनियन के विकास का इंजिन बना हुआ था। चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास कर रही थी अतः पिछले 20 वर्षों के दौरान चीन, जर्मनी से लगातार

मशीनरी, कार एवं केमिकल पदार्थों का भारी मात्रा में आयात करता रहा है। परंतु, अब परिस्थितियां बदल रही हैं क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भी हिचकोले खाने लगी है और चीन ने विभिन्न उत्पादों का जर्मनी से आयात कम कर दिया है। अतः अब जर्मनी अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बदली हुई परिस्थितियों में चीन, जर्मनी में निर्मित विभिन्न उत्पादों का आयात करने के स्थान पर वह जर्मनी का प्रतिस्पर्धी बन गया है और इन्हीं उत्पादों का निर्यात करने लगा है। दूसरे, पिछले लगभग 2 वर्षों से रूस ने भी ऊर्जा की आपूर्ति यूरोप के देशों को रोक दी है, रूस द्वारा निर्यात की जाने वाली इस ऊर्जा का जर्मनी ही सबसे अधिक लाभ उठाता रहा है। तीसरे, जर्मनी में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक अनुमान के अनुसार जर्मनी में आगे आने वाले एक वर्ष से कार्यकारी जनसंख्या में प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की कमी आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इससे उपभोक्ता खर्च पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चौथे, जर्मनी में नागरिकों की उत्पादकता भी कम हो रही है। जर्मनी में प्रत्येक नागरिक वर्ष भर में केवल 1300 घंटे का कार्य करता है जबकि ओईसीडी देशों में यह औसत 1700 घंटे का है। पांचवे, यूरोपीयन यूनियन में वर्ष 2035 में पेट्रोल एवं डीजल पर चलने वाले चार पहिया वाहनों के उत्पादन पर रोक लगाई जा सकती है जबकि इन कारों का निर्माण ही जर्मनी में अधिक मात्रा में होता है तथा जर्मनी की कार निर्माता कम्पनियों ने बिजली पर चलने वाले वाहनों के निर्माण पर अभी बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है। साथ ही, जर्मनी ने नवाचार पर भी कम ध्यान दिया है एवं स्टार्ट अप विकसित करने में बहुत पीछे रहा है आज इन क्षेत्रों में अमेरिका एवं चीन बहुत आगे निकल गए हैं एवं जर्मनी आज अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहा है। अतः जर्मनी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव आगे आने वाले लम्बे समय तक चलने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव भी जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है एवं अब पूरे विश्व में गैरवैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। आज प्रत्येक विकसित एवं विकासशील देश अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बनना चाहता है। अतः जर्मनी जैसे देशों से मशीनरी एवं कारों का निर्यात कम हो रहा है।

क्रमशः ...

नक्सल प्रभावितों की केन्द्रीय गृह मंत्री से भावुक मुलाकातः छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता की सराहना

नई दिल्ली/रायपुर. छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लगभग 70 नक्सल पीड़ितों का एक दल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मिला। नक्सल हिंसा से प्रभावित इन लोगों ने अपनी व्यथा साझा की और न्याय व पुनर्वास की माँग की। इस दल का नेतृत्व बस्तर शांति समिति ने किया, जो राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के लिए काम कर रही है।इनमें से कई लोगों ने नक्सलियों के हाथों अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, कुछ ने अपने अंग गंवाए हैं, और कुछ पूरी तरह से अपाहिज हो गए हैं। इस दल का नेतृत्व बस्तर शांति समिति द्वारा किया गया, जो राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के लिए काम कर रही है। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य नक्सल हिंसा से पीड़ित लोगों की पीड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था। पीड़ितों ने बताया कि नक्सली हमलों के कारण उनके जीवन में गंभीर व्यवधान आए हैं। इस मुलाकात के दौरान, गृह मंत्री ने नक्सल पीड़ितों की कहानियों को ध्यान से सुना और उनकी समस्याओं पर गंभीरता दिखाई। उन्होंने इन लोगों के संघर्ष और साहस की प्रशंसा की और आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुलाकात के दौरान नक्सल पीड़ितों ने गृह मंत्री को अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे नक्सल हिंसा ने उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसी ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, किसी ने अपने अंग गंवाए, और कई लोग अब भी

शारीरिक और मानसिक रूप से इन हमलों के जख्मों से जूझ रहे हैं। एक पीड़ित ने बताया, नक्सलियों के कारण हमने अपना सब कुछ खो दिया। अब हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मदद करेगी और हमें न्याय मिलेगा। गृह मंत्री ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे इन परिवारों का पुनर्वास हो सके और वे एक बार फिर सामान्य जीवन जी सकें।

जंतर मंतर पर पीड़ितों की आवाज़- गृह मंत्री से मुलाकात से पहले, नक्सल पीड़ितों का यह दल जंतर मंतर पर भी पहुँचा था, जहाँ उन्होंने अपनी समस्याओं को आम जनता के सामने रखा। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और शांति को प्राथमिकता दी जाए, और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। एक पीड़ित ने कहा, हमने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और विकास कार्यों से प्रेरित होकर अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने का साहस किया है। अब हमें उम्मीद है कि हमारे गाँवों में स्थायी शांति आएगी और हम अपने जीवन को फिर से सुधार पाएंगे।

आने वाली योजनाएँ- यह दल 21 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेगा। इस मुलाकात में नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायी शांति और विकास के लिए चर्चा की जाएगी। दल के सदस्य राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें सुरक्षा बलों की तैनाती, विकास कार्यों की गति बढ़ाने, और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की माँग की जाएगी।

इस मुलाकात के बाद नक्सल पीड़ितों में एक नई उम्मीद जागी है कि उनके संघर्ष और पीड़ा को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाएगा। सरकार उनके पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाएगी, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार का योगदान- नक्सल पीड़ितों ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यों से प्रभावित होकर अपनी बात दिल्ली तक लाने का साहस कर पाए हैं। राज्य सरकार ने जिस तरह से बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और सुरक्षा प्रयासों को प्राथमिकता दी है, उसने इन लोगों को यह हिम्मत दी कि वे अपनी आवाज़ दिल्ली में उठाएँ। छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता और सक्रियता से प्रभावित होकर, पीड़ितों ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में जिस प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और पुनर्वास के लिए काम किया गया है, वह काबिल-ए-तारीफ है। राज्य सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है, जिससे प्रभावित लोगों में नई उम्मीद जागी है। एक पीड़ित ने बताया, हमने अपने परिवार, अंग और जीवन की खुशियाँ खोईं, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों ने हमें यह हिम्मत दी कि हम अपनी बात देश की राजधानी दिल्ली तक ला सकें। मुख्यमंत्री साय ने न केवल हमारे दर्द को समझा, बल्कि हमें यह भरोसा दिलाया कि हमारे साथ न्याय होगा।

बुजुर्ग ने पेश की मिसाल, अस्पताल के लिए की जमीन दान देने की पेशकश

रायपुर। रायपुर के अश्विनी नगर में रहने वाले 91 वर्षीय गौरीशंकर अग्रवाल लंबे समय से वकालत के पेशे में संलग्न हैं। बौद्धिक क्षमता के धनी अग्रवाल छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा के उपर किताब भी लिख चुके हैं।

आज के समय में जब हर इंसान संपत्ति बनाने और बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, अग्रवाल ने इन सबसे उपर उठकर अपनी संपत्ति को राष्ट्रहित में दान करने की पेशकश की है। उन्होंने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की और अपनी मंशा के अनुरूप बलौदाबाजार जिले में स्थित अपनी 38 डिस्मिल की संपत्ति को जनहित में स्वास्थ्य कार्यों के इस्तेमाल के लिए अस्पताल बनाने के उद्देश्य से दान करने की इच्छा जताई। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अग्रवाल के इस फैसले की तारीफ करते हुए पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अग्रवाल की मंशा के अनुरूप आगे की कार्यवाही के लिए बलौदाबाजार कलेक्टर को निर्देश दिया है ताकि विधि सम्मत आगे की कार्यवाही की जा सके।

राइस मिलर्स का सरकार पर 1800 करोड़ बकाया

रायपुर। राज्य के 28 सौ राइस मिलर्स को प्रदेश सरकार से कस्टम मिलिंग का 1800 करोड़ रुपए लेना बकाया है। प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि सरकार से पांच सौ करोड़ रुपए तो बारदाना का ही लेना है। भुगतान नहीं होने के कारण राइस मिल मालिकों की आर्थिक स्थिति खराब हो चली है। अग्रवाल ने बताया कि लगभग दो हजार मिलें बंद हो गई है। राइस मिल मालिकों की समस्या का समाधान करने की दिशा में सरकार का कोई ध्यान नहीं है जबकि राज्य का राजस्व बढ़ाने में राइस मिलों की बड़ी भूमिका है। समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री व मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं परंतु विसंगतियों को दूर करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। अग्रवाल ने बताया कि परिवहन का ही पांच सौ करोड़ बचा है।

दिव्यांग विवेक को मिला वॉकर

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में दुर्घटना में पैर खोने वाले विवेक को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वॉकर भेंट किया। वॉकर पाकर विवेक अब चलने-फिरने लगे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान भी लौट आई है। विवेक ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने वॉकर प्रदाय किया हैं, इससे अब मुझे चलने में और अपना काम करने में परेशानी नहीं होगी। रायपुर के भनपुरी स्थित बुनियाद नगर निवासी श्री विवेक शर्मा एक दुर्घटना में एक पैर खो दिए।

वित्त मंत्री से चर्चा के बाद अधिकारी-कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित

रायपुर। डीए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 20 सितम्बर से हड़ताल पर जाने वाले थे। लेकिन वित्तमंत्री ओपी चौधरी से हुई दौर की चर्चा के बाद संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश व्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। राज्य के कर्मचारी केंद्र के सामान डीए की मांग कर रहे हैं। जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। दरसअल, राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष है। जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 20 सितम्बर को हड़ताल करने का ऐलान किया था। क्योंकि, भाजपा ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी देते हुए कहा था कि, वह केंद्र के समान डीए देगी और बकाया एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में अंतरित करेगी। लेकिन वर्तमान में राज्य के कर्मचारी और पेंशनर डीए के मामले में केंद्र के कर्मचारियों से 4 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। संयुक्त मोर्चा ने की थी हड़ताल की घोषणा-राज्य के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर 9 सितंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल करने की घोषणा की थी। लेकिन 2 सितंबर को मुख्य मंत्री से चर्चा में मिले ठोस आश्वासन में हड़ताल को 19 सितंबर स्थगित कर दिया गया। संयुक्त मोर्चा की ओर से कहा गया था कि, यदि 19 सितंबर तक डीए का आदेश जारी नही हुए तो 20 सितंबर को हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री चौधरी ने मोर्चा के प्रतिनिधियों को 13 सितंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित कर प्रदेश की वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को चार प्रतिशत डीए देने की सहमति व्यक्त की थी। लेकिन देय तिथि से डीए देने पर गतिरोध संयुक्त मोर्चा और शासन के बीच बना रहा। केंद्र के कर्मचारियों के साथ ही मिलेगा प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा डीए=वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री की आपसी चर्चा के बाद दूसरे दौर की चर्चा हेतु वित्त मंत्री के बुलाने पर मोर्चा के घटक संगठनों के प्रतिनिधियों की 17 सितंबर को देर रात्रि वित्तमंत्री के साथ दूसरे दौर की हुई। इस चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि, चार प्रतिशत डीए देने की घोषणा मुख्य मंत्री स्वयं अतिशीघ्र करेंगे.

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

21 सितंबर को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया

रायपुर। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और कवर्धा की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शनिवार 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कवर्धा के लोहारीडीह गया था। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस के नेतागण पुलिस अभिरक्षा में मृत प्रशांत साहू की अंत्येष्टि में शामिल हुये तथा परिजनों से भी मिले। परिजनों ने पुलिस के मारपीट के कारण प्रशांत की मौत होने का आरोप लगाया। लोहारीडीह घटना स्थल से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कांफ्रेंस में सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप गृह मंत्री के जिले में घटना होने के चलते गृह मंत्री को बर्खास्त करने मुख्यमंत्री से की मांग पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है, आम आदमी और सरकार में बैठे हुये लोगों के लिये अलग कानून है। लगातार हो रही अपराधिक घटनाओं को पुलिस रोक नहीं पा रही है। कचरू साहू का दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की रेंगाखार थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की मांग सरकार और पुलिस चाहती तो घर जलाने की घटना को रोक सकती थी, पूरे प्रदेश में भय का माहौल है।

भाजपा सरकार के कुशासन को छुपाने राजनैतिक पर्यटन कर रहे हैं

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि नक्सल मामलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। अपने सरकार की नाकामी को छुपाने प्रदेश के गृह मंत्री जंतर-मंतर में नक्सल पीड़ितों के जख्म का नुमाइश करके घड़ियाली आंसू बहा रहे है। विगत 9 महीने के दौरान कोई ठोस नक्सल नीति नहीं बना पाए। राहत, समर्पण, पुनर्वास और सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक संशय की स्थिति में है। केवल कागजी दावे और जुबानी खर्च के अलावा धरातल पर कोई ठोस नीति भाजपा की सरकार अब तक लागू नहीं कर पाई है। प्रदेश के गृह मंत्री खुद संसय की स्थिति में है। कभी कहते हैं कि नक्सलियों से वीडियो कॉल पर बात करेंगे, नक्सलियों से सलाह मांगने क्यू आर कोड और गूगल फॉर्म जारी करते हैं, कभी नक्सलियों के साथ लालभाजी खाकर नक्सलवाद खत्म करने की बात कहकर सुरक्षा बलों का मनोबल कम करते हैं। पिछले 1 माह के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चार-चार जवानों में प्रशासन की उपेक्षा से पीड़ित होकर आत्महत्या की है, हाल ही में एक जवान ने अपने दो साथियों जवानों की हत्या कर दी, गोली लगने से दो अन्य जवान घायल हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने अब

सूने मकान से हजारों रुपए के जेवर पार

रायपुर। शिवानंद नगर सेक्टर 3 खमतराई स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी तारकेश्वर प्रसाद 52 वर्ष शिवानंद नगर सेक्टर 3 खमतराई का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने आलमारी में रखे सोने-चांदी का जेवर पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 95 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अज्ञात टेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

रायपुर। ग्राम बिलाड़ी के सीजी ढाबा के पास अज्ञात टेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। जिससे युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसासार प्रार्थी अनुज यादव 43 वर्ष ग्राम पौसरी का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी अपने चाचा दूजराम यादव 45 वर्ष के साथ बाइक क्रमांक सीजी 04 टीआर 7255 से कहीं जा रहा था। तभी ग्राम बिलाड़ी के सीजी ढाबा के पास अज्ञात ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दिया।

सट्टा खिलाते दो युवक गिरफ्तार

रायपुर। सिविल लाइन पुलिस ने मधुपिल्ले चौक के पास दबिश देकर सट्टा खिलाते दो युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सट्टा-पट्टी सहित नकदी 9500 व मोबाइल जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन पुलिस के टीम ने मुखबिर की सूचना पर मधुपिल्ले चौक के पास आरोपी सैय्यद सलमान 22 वर्ष व एक अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से सट्टा-पट्टी सहित नकदी 9500 रुपए व मोबाइल जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

गांजा के साथ दो युवक गिरफ्तार

रायपुर। गोलबाजार एवं मोवा पुलिस ने गांजा के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 11 किलो 227 ग्राम गांजा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार गोलबाजार पुलिस ने डीकेएस अस्पताल के पीछे पार्किंग के पास दबिश देकर आरोपी सुमीत सिंह 21 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से बैग में रखे 8 किलो 180 ग्राम गांजा जब्त किया है। जिसकी कीमत करीब 40 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं मोवा पुलिस ने मोवा ओव्हरब्रीज के पास आरोपी रविन्द्र पासवान 26 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से बैग में रखे 3 किलो 47 ग्राम गांजा जब्त किया है।

होटल बुलाकर महिला से किया अनाचार, गिरफ्तार

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर रायपुर लखन पटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में महिलाओं/बच्चियों से संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में पीडिता ने लिखित शिकायत पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि रायपुर में एक होटल में काम के दौरान उसकी पहचान आरोपी प्रिंस निवासी गोवा से हुई थी, जो दोनो अक्सर फोन पर बाते करते थे, आरोपी प्रिंस द्वारा इसे फोन कर कुछ जरूरी काम है रेल्वे स्टेशन के पास आ जाओ बोला। तब पीडिता आरोपी प्रिंस से मिलने रेल्वे स्टेशन आई तो आरोपी प्रिंस पीडित्ता को एक होटल में ले जाकर तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ कहकर जरबदस्ती करने लगा। इसके द्वारा मना करने पर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा शादी करने बोलने पर आरोपी आगरा चलते है वही शादी करेंगे कहकर आगरा ले गया जहां पर भी पीडिता ने आरोपी को शादी की बात कही जो टालमटोल करने लगा और वाद विवाद कर मारपीट किया, और आरोपी पीड़िता के घर पहुँचकर जान से मारने की धमकी देने लगा और शादी नहीं करूंगा जो करना है कर लो कहकर धमकी दिया कि शिकायत आवेदन पर थाना गंज रायपुर में दिनांक 18.09.2024 को आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 335/2024 धारा 69, 115(2), 351(2) भारतीय न्याय सहिता 2023 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पीएम सूर्यघर योजना में तेजी लाने के निर्देश, विद्युत सेवा भवन में हुई प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक

देश में 14 हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्यः दयानंद

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा (रिनीवेबल एनर्जी) की दिशा में विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 14151 मेगावाट क्षमता के सोलर और पंप स्टोरेज हाइडल प्लांट लगेंगे। इसके तहत पीएम सूर्यघर योजना, पीएम कुसुम योजना, फ्लोटिंग सोलर योजनाओं पर काम चल रहा है। इन योजनाओं की प्रदेश स्तरीय समीक्षा ऊर्जा सचिव एवं छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज के चेयरमेन पी. दयानंद ने की।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप पूरे देश में नवीकरणीय

ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से कार्य प्रारंभ किये गए हैं। जिसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में इस दिशा में संभावनाओं पर ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोतों से वर्ष 2030 तक 14 हजार 151 मेगावाट क्षमता के संयंत्र लगाए जाने हैं। श्री दयानंद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं को अमली-जामा पहनाया जाए। पॉवर कंपनी के डगनिया स्थित मुख्यालय सेवाभवन में आयोजित बैठक में ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव श्री सुनील कुमार जैन सहित पावर कंपनी के प्रबंध निदेशकगण सर्वश्री भीमसिंह कंवर (वितरण), एसके कटियार (उत्पादन) एवं आरके शुक्ला (पारेषण) विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजना की बारिकियों को बताया गया। इसमें पूरे प्रदेशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों से आए कार्यपालक निदेशक, मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता को उनके क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा करने तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्यघर एवं अन्य रूफटाफ योजना के माध्यम से 2415 मेगावाट, पीएम कुसुम योजना में 1316 मेगावाट, फ्लोटिंग सोलर से 600 मेगावाट, ओपन एक्सेस से 1890 मेगावाट और हाइड्रो एवं पंप स्टोरेज तकनीक से 7930 मेगावाट क्षमता के संयंत्र लगाए जाएंगे। इन योजनाओं से प्रदेश में एक लाख 19 हजार 371 रोजगार सृजन होंगे। पावर पाइंट प्रजेंटेशन एसई एम बिंबीसार ने दिया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक सर्वश्री वीके साय, आरए पाठक, संदीप वर्मा, एम. जामुलकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

छह सालों में पूरा करने का लक्ष्य

वर्ष	लक्ष्य (मेगावाट)
2024-25-	1157
2025-26-	2385
2026-27-	4252
2027-28-	6321
2028-29	6661
2029-30-	14151

फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनकी छवि धूमिल करने और छलपूर्वक आर्थिक लाभ कमाने के आरोप में राजस्थान के रामनगर तहसील, फुलेरा निवासी अंतर्राज्यीय आरोपी राकेश परिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं।इससे पहले एक अन्य आरोपी को अलवर, राजस्थान से गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी आईडी बनाई थी, जिसके जरिए वे लोगों को फ्रेंड्स ऐड करके उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे थे।

साइबर थाने में मामला दर्ज- इस घटना की जानकारी मिलते ही

रेंज साइबर थाना रायपुर में आईटी एक्ट की धारा 66(ष्ट), 336(3), और 340 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, अमरेश मिश्रा ने घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम को तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे।

तकनीकी विश्लेषण से हुई गिरफ्तारी-साइबर थाने की टीम ने फर्जी आईडी का तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की और राजस्थान के रामनगर में उसे लोकेट किया। पुलिस टीम ने राजस्थान पहुंचकर आरोपी की पतासाजी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। राकेश परिहार ने 2022 में मुख्यमंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष की फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाने की बात स्वीकार की है। यह क्षेत्र पहले से ही ऐसे मामलों के लिए कुख्यात है.

जहां लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी आईडी बनाते हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.